साध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष–01 अंक–185 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

सु-विचार

" जरूरत से ज्यादा सोचना भी आपकी खुशियां छीन लेता है...!! "

अज्ञात...

1000 क्विंटल से अधिक चावल में गड़बड़ी : शासकीय उचित मूल्य दुकान के अध्यक्ष गिरफ्तार, अपराध दर्ज

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेक्टर–07 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1007.51 क्विंटल चावल की कमी पाए जाने पर थाना भिलाई नगर पुलिस ने संचालक/अध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। खाद्य विभाग की शिकायत पर कलेक्टर दुर्ग के आदेश पर गठित जांच समिति ने 24 जुलाई 2024 को दुकान आईडी–431004118 का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में अभिलेखों और ऑनलाइन स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया।

1007 क्विंटल की निकली कमी

जांच में वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो मिली, लेकिन स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। भौतिक सत्यापन में दुकान में सिर्फ 26.50 क्विंटल चावल मिला, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 1034.01 क्विंटल दर्शाया गया था। इस तरह 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मौके पर पंचनामा तैयार कर कथन दर्ज किए गए।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कई कंडिकाओं और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 401/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण और साक्ष्य संकलन के बाद दुकान के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत, उम्र 63 वर्ष, निवासी सेक्टर–07 भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर कर लेखा–जोखा सही नहीं रखा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया। प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जब्त कर जांच जारी है।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनियमित वितरण या किसी भी गड़बड़ी की सूचना तत्काल पुलिस या खाद्य विभाग को दें, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

जंतर–मंतर पर बढ़ा आक्रोश

बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी छात्रों के समर्थन में उतरे

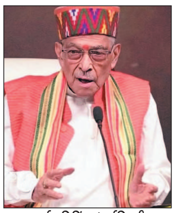

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में जंतर–मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर गतिरोध गहराता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी खुलकर छात्रों का समर्थन किया है।

"छात्रों की चिंताएं वास्तविक हैं": मुरली मनोहर जोशी

भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर छात्रों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि देश के कोने–कोने से आए युवाओं की चिंताएं पूरी तरह जायज हैं। इसे सिर्फ "कानून–व्यवस्था" का मुद्दा मानकर बलपूर्वक नहीं निपटाया जाना चाहिए। जोशी ने प्रदर्शनकारी छात्राओं और युवाओं पर हुए पुलिस बल प्रयोग पर भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कदमों से "विकसित भारत" के लक्ष्य से हम दूर होते जाएंगे।

संसद से सड़क तक विपक्ष का हंगामा संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी हंगामा किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने राहुल गांधी के 5 सुनहरी बाग स्थित आवास से गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो" के नारे गूंजते रहे।

सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी के आवास और आसपास के इलाके में कड़ी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि पास में ही गृह मंत्री अमित शाह का आवास भी है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन सड़क से संसद तक जारी रहेगा।

देशभर में फैला आंदोलन

यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू, धर्मशाला, जयपुर, जोधपुर और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से छात्रों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प और लाठीचार्ज की भी सूचना है।

सरकार–छात्र वार्ता पर गतिरोध : केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि वे किसी मंत्री के आवास या सरकारी दफ्तर में बात नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि सरकार या तो जंतर–मंतर पर आए या किसी निष्पक्ष स्थान पर मीटिंग रखे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार पिछले 12 सालों से दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा न लेने की नीति पर कायम है। सरकार का मानना है कि इस्तीफे से "गलती स्वीकार करने" का संदेश जाएगा। इसी कारण सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और री–एग्जाम जैसे कदमों से स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी का आधी रात को संदेश : "पेपर लीक छात्रों के लिए पीड़ादायक, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा"

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार आधी रात को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर छात्रों और अभिभावकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की संवेदना जताते हुए कई बड़े फैसलों की घोषणा की।

"लाखों छात्रों का दर्द हम समझते हैं"

पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक हैं। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह समझती है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पिछले ढाई महीने में कड़े कदम

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इस दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही लगभग 22 लाख छात्रों का शैक्षणिक सत्र खराब न हो, इसके लिए प्रभावित परीक्षाओं का कम से कम समय में पुनर्नियोजन किया गया और उनके नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और नया कानून लाने की तैयारी

पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दोषियों को त्वरित और सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। इसके साथ ही पेपर लीक से जुड़े कड़े प्रावधानों वाला एक नया बिल का मसौदा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस बिल को पहले कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा और फिर संसद के आगामी सत्र में पास कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके। पीएम के इस संदेश को सरकार द्वारा आंदोलनरत छात्रों को मनाने और विश्वास दिलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

22 लाख छात्रों का साल बचाने के लिए परीक्षा पुर्ननियोजित

26वें दिन टूटा सोनम वांगचुक का अनशन

केंद्र ने मानी 5 बड़ी मांगें, पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटका पेंच, आंदोलन खत्म होगा या जारी रहेगा, इस पर संशय

NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक के विरोध में जंतर–मंतर पर पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने बुधवार आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात कर सरकार का लिखित आश्वासन पत्र सौंपा। इसके बाद वांगचुक ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की।

स्वास्थ्य नहीं, हिंसा का डर बना कारण

डॉक्टरों के अनुसार 26 दिन के अनशन में वांगचुक का वजन करीब 11 किलो कम हो गया था और सेहत काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन अनशन तोड़ने की वजह उन्होंने स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आंदोलन में हिंसा फैलने की आशंका बताई। वांगचुक ने कहा, "आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व हिंसा भड़काना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो अब तक की शांतिपूर्ण तपस्या बेकार चली जाती।" उन्होंने बताया कि 65 सांसदों और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी।

सरकार ने मानी ये 5 बड़ी मांगें

सरकार और वांगचुक के बीच हुई सहमति के बाद केंद्र ने कई अहम फैसले लिए हैं :

1. FIR नहीं होगी : प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई पुलिस केस दर्ज नहीं होगा और न ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. बड़ा प्रशासनिक बदलाव : उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाया गया है।
3. फास्ट ट्रैक कोर्ट : पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे।
4. मुआवजे का ऐलान : पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा।
5. संसद में चर्चा : सरकार ने संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने का आश्वासन दिया है।

पिछले 24 घंटों में सरकार की सक्रियता भी तेज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि युवाओं का भविष्य उनकी पहली प्राथमिकता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

क्या खत्म हुआ आंदोलन? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटका पेंच

वांगचुक के अनशन खत्म करने के बावजूद जंतर–मंतर पर डटे छात्र संगठनों का आंदोलन अभी जारी है। आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सूत्रों के अनुसार वांगचुक ने सरकार को जो शर्तों की सूची सौंपी थी, उसमें मंत्री का इस्तीफा प्राथमिकता में नीचे था। वहीं सरकार का रुख है कि पिछले 12 सालों में दबाव में आकर किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया है, क्योंकि इससे "चूक स्वीकार करने" का संदेश जाता है। जंतर–मंतर पर मौजूद छात्रों का कहना है कि, "वांगचुक जी के अनशन तोड़ने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक डटे रहेंगे।"

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम परिवारों से जुड़े इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बिना देरी राहत के कदम उठाए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी न होने तक आंदोलन की आग पूरी तरह बुझती नहीं दिख रही। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार और छात्रों के बीच अगली बातचीत में कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं।

राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का मार्च, अमित शाह–धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी

प्रधानमंत्री का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, छात्रों ने कहा "इस्तीफा दो"

देशभर में NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने का ऐलान किया, जिसे छात्रों और विपक्ष ने "नाकाफी" करार दिया।

गांधी स्मृति तक विपक्ष का मार्च

दिन की शुरुआत INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक से हुई। राहुल गांधी के 5 सुनहरी बाग स्थित आवास पर मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बनाई। इसके बाद सभी नेता तीन बसों में सवार होकर गांधी स्मृति की ओर मार्च के लिए निकले।

विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो" के नारे लगाते रहे। मार्च के रास्ते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पड़ने के कारण दिल्ली पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती की गई। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

पीएम का ऐलान : फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे

पेपर लीक पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि "युवाओं का भविष्य सरकार की पहली प्राथमिकता है।" उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। लेकिन छात्रों और विपक्ष ने इस ऐलान को सिरे से खारिज कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ सजा का नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में सुधार का है।

छात्रों की 3 बड़ी मांगें

1. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
2. परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार
3. प्रभावित छात्रों से सरकार सार्वजनिक माफी मांगे

छात्र संगठनों ने सरकार की बातचीत की पेशकश भी ठुकरा दी। उनका कहना है कि बातचीत जंतर–मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर हो और उसकी ठोस समय–सीमा तय की जाए।

आंकड़े डराने वाले : 24 साल में 45 बड़े लीक

रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 23–24 सालों में देश में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली 45 बड़ी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। इससे करीब 3 करोड़ 86 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इन मामलों में कुल 10,658 गिरफ्तारियां हुईं, 925 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मामलों में सजा हो पाई है। दोनों मामलों की जांच CBI कर रही थी और सजा मिलने में 15 से 23 साल लग गए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का "रियलिटी चेक"

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से न्याय की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। पूर्व के अध्ययनों में पाया गया है कि कई राज्यों में मंजूर कोर्ट की तुलना में बहुत कम कोर्ट शुरू हो पाए और निपटारे की रफ्तार धीमी रही। अभी भी निचली और जिला अदालतों में 20 से 30 प्रतिशत जजों के पद खाली हैं। फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा संसद से सड़क तक गरमाया हुआ है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन छात्र इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में गतिरोध और बढ़ने के आसार हैं।

कोतवाली–साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई : मोटर साइकिल चोरी के 9 मामले खुले

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 चोरी के मामलों का खुलासा किया है। आरोपियों से 1 लाख 55 हजार रुपये कीमत की 7 मोटर साइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

जनवरी से जून के बीच हुई थी चोरियां : 10 जनवरी 2026 से 07 जून 2026 के बीच कोतवाली क्षेत्र के जय स्तंभ चौक, गोल बाजार, भदौरिया चौक, रामनगर बिजली ऑफिस के पास, अम्बेडकर चौक और बजरंगपुर में मोटर साइकिल चोरी की घटनाएं हुई थीं। प्रार्थियों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 8 अपराध क्रमांक 45/26, 59/26, 74/26, 95/26, 247/26, 249/26, 255/26, 301/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज किए गए थे। इसी तरह थाना बसंतपुर में भी 1 मामला दर्ज था।

सीटीवी और मुखबिर से मिली सफलता : कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह और साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में मिले सुराग और मुखबिर की सूचना पर टीम कबीरधाम जिले रवाना हुई और घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ा। वीरू सारथी, पिता रामप्रसाद सारथी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सारथी पारा गोपीबंद मोहल्ला वार्ड–3, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम, संदीप सत्यवंशी, पिता अशोक सत्यवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम दुल्लापुर रानी सागर, थाना कोतवाली, जिला कबीरधाम शामिल है। पूछताछ में दोनों ने कोतवाली क्षेत्र की चोरियां करना स्वीकार किया। उनके कब्जे से 6 बाइकें बरामद हुईं। बसंतपुर थाने के प्रकरण में चोरी गई 1 बाइक भी बरामद की गई।

बरामद वाहन : सीजी 08 वाय–1807, सीजी 08 वाय–1286, सीजी 08 एपी–8317, सीजी 08 जी–2194, सीजी 04 एनजी–1514, सीजी 24 जे–8958 और सीजी 04 टीयू–5488। कुल कीमत 1.55 लाख रुपये। आरोपियों ने बताया कि अपराध क्रमांक 59/26, 94/26, 301/26 में चोरी की 3 बाइकें सीजी 08 बीबी–3461, सीजी 08 एच–1821, सीजी 08 डब्ल्यू–7625 पेट्रोल खत्म होने या खराबी के कारण रास्ते में छोड़ दी थीं। उन्हें लावारिस हालत में बरामद कर न्यायालय के आदेश पर प्रार्थियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

आदतन चोर हैं दोनों : दोनों आरोपी आदतन चोर हैं। वीरू सारथी के खिलाफ थाना कवर्धा में चोरी–नकबजनी के 4 मामले और संदीप सत्यवंशी के खिलाफ 2 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक संजीव मालेकर, नंदनी ठाकुर, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल कुमार, अफजल खान, किशोर यादव, साइबर सेल के बसंत राव, परिवेश वर्मा, हरिश ठाकुर, मोहन साहू, मनीष वर्मा, प्रख्यात जैन, पुनेश्वर साहू, खिलेश्वर साहू, कमलेश्वर साहू और अभिषेक साहू की सराहनीय भूमिका रही।

अंतर्राज्यीय मोटर साइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश

राजनांदगांव। साइबर थाना और थाना लालबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय मोटर साइकिल चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से अलग–अलग जगहों से चोरी की 6 मोटर साइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। प्रार्थी शुभम यादव निवासी पेण्ड्री ने 08.07.2026 को शेरे पंजाब ढाबा के पास खड़ी अपनी हीरो स्प्लेंडर CG 08 AR 1062 चोरी होने की रिपोर्ट थाना लालबाग में दर्ज कराई थी। इस पर अपराध क्रमांक 287/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान साइबर सेल से मिले सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने पेण्ड्री हाईवे स्थित देवांगन ढाबा के पास घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा।

महाराष्ट्र और एमपी से जुड़े हैं तार : पूछताछ में आरोपियों ने लालबाग से 1 बाइक के अलावा रायपुर शहर से 4 और आमगांव जिला गोंदिया महाराष्ट्र से 1 मोटर साइकिल चोरी करना स्वीकार किया। सभी 6 बाइकें बरामद कर ली गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी की बाइकों की पहचान छिपाने के लिए मूल नंबर प्लेट हटाकर फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते थे और उन्हीं का उपयोग करते थे। एक आरोपी के पास चोरी की बाइक होने की जानकारी के बावजूद उसे रखना भी पाया गया।

ये हुए गिरफ्तार : पंकज मंडिया, उम्र 19 वर्ष, निवासी सांवरीटोला, थाना रावणवाड़ी, जिला गोंदिया महाराष्ट्र, प्रतीक गयगये, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांवरीटोला, थाना रावणवाड़ी, जिला गोंदिया महाराष्ट्र, कमलेश नखाते, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम लाडसा, थाना लांजी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2), 336(3), 238, 317(2), 3(5) के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अन्य चोरी के मामलों में भी आरोपियों की संलिप्तता की जांच कर रही है।

ढौर में गोदभराई, अन्नप्राशन और सुपोषण वृक्षारोपण, बाल विवाह मुक्ति की दिलाई शपथ

महिला-बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने आंगनबाड़ी केंद्र धौर-4 के प्रांगण में सुपोषण वृक्ष मुनगा का पौधा लगाया

नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा

धौर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत धौर के प्राथमिक विद्यालय क्रमांक-2 के प्रांगण में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सभापति जितेंद्र यादव ने की। विशेष अतिथि के रूप में जनपद पंचायत दुर्ग के सभापति गोकुल वर्मा उपस्थित रहे। अन्य अतिथियों में सरपंच लता साहू, उप सरपंच घनश्याम साहू और विधायक प्रतिनिधि अशोक मंडारे शामिल हुए।

सुपोषण वृक्षारोपण और सामग्री वितरण : मुख्य अतिथि डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने आंगनबाड़ी केंद्र धौर-4 के प्रांगण में सुपोषण वृक्ष मुनगा का पौधा लगाया। जिला पंचायत सभापति जितेंद्र यादव और जनपद पंचायत सभापति गोकुल वर्मा ने भी आंगनबाड़ी परिसर में पौधरोपण किया। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत 3 गर्भवती महिलाओं गीता, सुरेखा और सुनीता की गोदभराई की गई। वहीं 6 माह पूर्ण कर चुके 2 बच्चों मायरा और नितिन का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। आंगनबाड़ी के बच्चों को पानी की बोतल और कलर पेंसिल का वितरण भी किया गया।

अतिथियों ने की योजनाओं की सराहना : डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गोदभराई, अन्नप्राशन और बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी देशलहरे के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देकर उन्हें शाला प्रवेश के लिए तैयार करती हैं। आप सभी हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। जिला पंचायत सभापति जितेंद्र यादव ने कहा कि महतारी वंदन, मातृत्व वंदना और पोषण आहार जैसी शासकीय योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। उन्होंने विभाग को शुभकामनाएं दीं।

बाल विवाह मुक्ति की शपथ : दुर्ग ग्रामीण परियोजना अधिकारी उषा झा ने बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने को लेकर संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद जितेंद्र यादव ने उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पयर्वेक्षक चंद्रकला शर्मा, कंचन गौतम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी देशलहरे, शकुन चित्ररेखा, वीणा साहू, मीना मंडारे, सुमन टंडन, हेमा चंद्रवंशी, शिक्षक-शिक्षिकाएं, पालक, ग्रामीण और बच्चे गोदावरी, मिथिलेश, मंजू, सुधा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

खास खबर

एसएमएस-3 में नए हॉट मेटल लैडल प्रीहीटर और वैकल्पिक सीओजी लाइन कमीशन, इन-हाउस तकनीक से बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-3 में पूर्णतः इन-हाउस संसाधनों से विकसित नए हॉट मेटल लैडल प्रीहीटर और वैकल्पिक कोक ओवन गैस हेडर लाइन की सफल कमीशनिंग की गई है। इस तकनीकी उपलब्धि से संयंत्र की उत्पादन क्षमता, परिचालन दक्षता और सुरक्षा मानकों को मजबूती मिलेगी। परियोजना के पूरा होने से रखरखाव कार्यों के दौरान भी उत्पादन बाधित नहीं होगा और संयंत्र की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

दो बड़े तकनीकी सुधार : एसएमएस-3 में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनमें

समर्पित डीएन-350 हेडर लाइन और नया लैडल प्रीहीटर: इसके जरिए लैडल बे और नए प्रीहीटर को निर्बाध गैस आपूर्ति मिल रही है। इससे लैडल कम समय में तैयार हो सकेंगे और परिचालन बेहतर होगा।

वैकल्पिक सीओजी हेडर लाइन: यह लैडल ड्रायर सर्किट को निरंतर और स्थिर गैस आपूर्ति देगी। इससे प्रतिदिन के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के अनुसार पर्याप्त संख्या में तैयार लैडल उपलब्ध रहेंगे।

रेडंडेंसी से घटेगा डाउनटाइम : नई ड्यूल-हेडर प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। अब लैडल ड्रायर सर्किट के नियमित अनुरक्षण के दौरान भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इससे अनावश्यक डाउनटाइम कम होगा और संयंत्र की उत्पादकता तथा परिचालन दक्षता में सीधा सुधार आएगा।

इन-हाउस टीम की उपलब्धि : यह परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र की इन-हाउस इंजीनियरिंग क्षमता और नवाचार का उदाहरण है। परियोजना की संकल्पना से लेकर सफल क्रियान्वयन तक का कार्य मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस-3 त्रिभुवन बैठा के नेतृत्व में पूरा हुआ।

इसमें महाप्रबंधक ऑपरेशन पी. के. अग्रवाल, महाप्रबंधक मेंटेनेंस पीके सतपथी, महाप्रबंधक मैकेनिकल संजीव कुमार मिश्रा, कन्वर्टर मैकेनिकल टीम से उप महाप्रबंधक राकेश वृष्णवंशी, वरिष्ठ प्रबंधक चंदन चतुर्वेदी और कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल टीम से उप महाप्रबंधक रजत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कल से 29 जुलाई तक होगा पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण का होगा आयोजन

दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में 22 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को और अधिक सशक्त, संगठित तथा जनसेवा केन्द्रित बनाना था, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि विधिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब न्याय की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को नए उत्साह, नई कार्यशैली एवं नई जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर्स न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से ही विधिक सहायता, जनजागरूकता एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकता है। बैठक के दौरान मुख्य रूप से 25 जुलाई से 29 जुलाई, 2026 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के चतुर्थ तल में स्थित नवीन सभागार में आयोजित होने वाले पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। सचिव द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित पाँच ग्रामों कुथरेल, निकुम, घुघसीडीह, अरसनारा एवं ननकट्ठी के सामुदायिक मध्यस्थ (मीडिएटर)

स्कूल रिकॉर्ड में जाति संशोधन की मांग अभिभावक ने दिया जनदर्शन में आवेदन

पट्टा में नाम परिवर्तन नहीं होने से योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 109 आवेदन प्राप्त हुए।

खुर्सीपार भिलाई निवासी अभिभावक ने अपनी पुत्री के स्कूल के दाखिल-खारिज रिकॉर्ड में दर्ज जाति के स्थान पर वास्तविक जाति दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने बताया गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश जाति दर्ज हो गया था। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। स्कूल रिकॉर्ड में संशोधन नहीं होने पर भविष्य में छात्रवृत्ति, आरक्षण एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ग्राम थनौद के किसानों ने भारतमाला सड़क निर्माण से फसल नुकसान की शिकायत की। किसानों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी कृषि भूमि की मेड़ें समतल कर दी गईं, बाड़ और पोल हटा दिए गए तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि घेर ली गई, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पहली ही बारिश में खेतों का कटाव हुआ, मुरुम और मलबा खेतों में भर गया जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने उचित जल निकासी की व्यवस्था कराने, प्रभावित भूमि का सुधार कराने व मुआवजे की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एनएचएआई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वैशाली नगर निवासी ने जनदर्शन में आवेदन देकर अपने आवासीय पट्टे में नाम परिवर्तन कराने की मांग की है। आवेदक ने बताया कि घर का पट्टा उनके बड़े भाई के नाम पर है। उनके बड़े भाई का वर्ष 2022 में निधन हो गया। इसके बाद भी पट्टा उनके नाम पर दर्ज नहीं हो सका है। नाम परिवर्तन नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की नियुक्ति

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन पदस्थापना की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीन अनुविभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत महेश सिंह राजपूत, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) का दायित्व सौंपा गया है। लवकेश कुमार ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी क्रम में उत्तम कुमार ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रकाश सोनी, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-3 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 का नवीन प्रभार प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को जिला चिकित्सालय दुर्ग के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोजनावकाश के दौरान सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारियों ने रैली निकालकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की एक प्रति कलेक्टर दुर्ग को भी प्रेषित की गई।

संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम, उप प्रांताध्यक्ष प्रमेश पाल, संभागीय अध्यक्ष अजय नायक, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता, कायर्कारी अध्यक्ष खिलावन चंद्राकर, अस्पताल संयोजक राघवेंद्र साहू, महामंत्री लक्ष्मीकांत धोटे तथा सचिव भूपेश उपाध्याय ने संयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सभी कैडरों की वेतन विसंगति दूर करना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति देना, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग एवं संविदा व्यवस्था समाप्त करना, प्रदेश के अस्पतालों का निजीकरण रोकना, जीवन दीप समिति के कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करना शामिल है।

प्रदर्शन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती जैकलीन डान, जिला अस्पताल दुर्ग की श्रीमती मंजू राय, कविता साहू, नर्सिंग संयोजक शिवेंद्र दानी, सुपेला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती सुशीला सिंह, संयुक्त सचिव धनीराम ठाकुर, निकुम अध्यक्ष यामनी नेताम, जीवन दीप समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सहित बड़ी संख्या में नर्सिंग, लैब, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य पयर्वेक्षक, वाहन चालक, बीईटीओ, चतुर्थ श्रेणी, संविदा, जीवन दीप समिति एवं ठेका कर्मचारियों ने भाग लिया।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

बीएसपी के बीआरएम में 'शाबाश योजना' के तहत उत्कृष्ट कार्मिक किए गए सम्मानित

मुख्य महाप्रबंधक योगेश शास्त्री ने कर्मचारियों को प्रदान किए प्रशस्ति प्रमाण-पत्र

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के बार एवं रॉड मिल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को 'शाबाश योजना' के अंतर्गत सम्मानित किया गया। विभाग में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष बार एवं रॉड मिल योगेश शास्त्री ने चयनित कार्मिकों को प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक शाश्वत मोहंती, समीर पांडे, शिखर तिवारी और तुषार श्रीखंडे भी उपस्थित रहे।

उत्कृष्टता और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य : समारोह को संबोधित करते हुए योगेश शास्त्री ने कहा कि 'शाबाश योजना' का उद्देश्य कार्य संस्कृति में उत्कृष्टता, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और सुरक्षित कार्य व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने सम्मानित कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि इन कार्मिकों ने अपने समर्पण और जिम्मेदारी से अन्य कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विभाग की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्मिकों में बढ़ा उत्साह : सम्मानित कार्मिकों ने प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान से उनका मनोबल बढ़ा है और वे आगे भी पूरी निष्ठा के साथ काम कर बार एवं रॉड मिल की उत्पादन उत्कृष्टता और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

क्या है 'शाबाश योजना' : भिलाई इस्पात संयंत्र समय-समय पर 'शाबाश योजना' के तहत उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, नवाचार, गुणवत्ता, सुरक्षा उत्कृष्टता और कार्यस्थल पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले कार्मिकों को सम्मानित करता है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ संयंत्र में उत्कृष्टता की कार्य संस्कृति को और मजबूत करना है।

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

23 दुकानदारों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 2450 रूपये का अर्थदण्ड

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. अचर्ना चौहान के मार्गदर्शन में विगत 21 जुलाई को कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत थाना जामगांव आर क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें विद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधानों का निरीक्षण किया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेल्हारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरवाय, जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटरेल परिसर के आस-पास उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ब एवं 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने वालों पर समझाईश के साथ-साथ चालानी कार्यवाही की गई तथा उन्हें भविष्य में कानून का पालन करने के निर्देश दिये हैं, उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कुल 23 चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 2 हजार 450 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

धारा 6अ के अंतर्गत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 6ब के तहत स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध एवं धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस चालानी कार्यवाही में औषधि निरीक्षक श्रीमती जागेश्वरी साहू, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रिचा शर्मा, पुलिस विभाग से आरक्षक संतोष गुप्ता, मोहम्मद शमीम, पंकज एवं स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती कविता ताम्रकार उपस्थित थे।

तालाब के आसपास कचरा फेंकने वालों पर निगम की कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं तालाबों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त के प्रातः भ्रमण के दौरान जोन-3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32, दुर्गापारा स्थित तालाब के आसपास नागरिकों द्वारा कचरा फेंके जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कचरा फेंकने वाले नागरिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

आयुक्त के निर्देश के परिपालन में जोन-3 के निगम अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर तालाब के आसपास कचरा फेंकने वाले नागरिकों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही निगम कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को समझाइश देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों एवं तालाब के आसपास कचरा न फेंके चलाए जा रहे डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन गाड़ियों के कर्मचारियों को दें। निगम अमले ने नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने तथा तालाब एवं उसके आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन 14 अगस्त तक : दुर्ग। एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा योजना के तहत जिला एवं विख स्तरीय कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला स्तर पर कृषि में 02 कृषकों, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन में एक-एक कृषकों कुल 5 प्रति कृषक को 25 हजार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। विख स्तर पर कृषि में 9, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन में 2-2 कृषकों कुल 15 उत्कृष्ट प्रति कृषक को 10 हजार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदन पत्र एनआईसी दुर्ग की वेबसाइट तथा कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के विख एवं जिला कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन दस्तावेज एवं गतिविधियों के फोटोग्राफ सहित विख एवं जिला कार्यालय में 14 अगस्त 2026 तक जमा किए जा सकते हैं।

पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएं : उपमुख्यमंत्री साव

कोरबा प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, उप मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब को 20 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कोरबा

कोरबा प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, रामपुर (कोरबा) में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कोरबा प्रेस क्लब को 20 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की। विधायक प्रेमचंद पटेल और फूलसिंह राठिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कोरबा प्रेस क्लब की पहचान राज्य स्तर पर है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी गरिमा बनाए

रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष, जिम्मेदार और तथयपरक पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करें। नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के दौर में पत्रकारिता के स्वरूप में बदलाव आया है। ऐसे समय में अनुभवी और युवा पत्रकारों के समन्वय से पत्रकारिता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा पत्रकार इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, जो समाज में जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का कार्य

कर रहे हैं। उन्होंने कोरबा प्रेस क्लब की गतिविधियों और समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की।

समारोह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पत्रकार सदैव निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। जनसरोकारों और शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता निष्पक्षता, जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकारों के साथ की जानी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती में मीडिया की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में कोरबा प्रेस क्लब के संरक्षक कमलेश यादव, अध्यक्ष नौशाद खान, उपाध्यक्ष राजकुमार शाह, सचिव दिनेश राज, उप सचिव हरीश तिवारी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव तथा कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार मिश्रा (मिट्ठू), नवाब हुसैन एवं आकाश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में कोरबा जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। समारोह में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी एवं बिलासपुर प्रेस क्लब के अभिजीत मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

खास खबर

छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ हुआ ऐतिहासिक एमओयू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू, 10 संवेदनशील जिलों में होगा पहले चरण का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कायर्शाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आईआईटी मद्रास के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डेमोग्राफि क्स

इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से कमी लाना है। कायर्शाला में अधिकारियों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय और कम लागत वाले अभियांत्रिकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। संजय प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लैक स्पॉट की समय पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जाएंगे।

प्रथम चरण में राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा कायर्योजना तैयार की जाएगी।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति होती है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षित सड़क व्यवस्था विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। यह पहल सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने कहा कि संजय प्लेटफॉर्म से दुर्घटना संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होगा। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर दुर्घटनामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान किया। कायर्शाला में चयनित 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, डीटीओ, एनआईसीसी के जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा-आधारित योजना एवं त्वरित हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रभावी कमी आएगी।

जटिल सर्जरी से खुला मुंह, आयुष्मान योजना से मिला नि :शुल्क उपचार

रायपुर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध सिम्स अस्पताल, बिलासपुर के दंत चिकित्सा विभाग ने एक दुर्लभ एवं जटिल शल्य चिकित्सा कर 24 वर्षीय युवक के बचपन से बंद जबड़े को सफलतापूर्वक खोलने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अविकसित निचले जबड़े के कारण वर्षों से सामान्य रूप से मुंह नहीं खोल पाने वाले मरीज का आधुनिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसे निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया।

मुंगेली जिले के अमली कापा निवासी 24 वर्षीय युवक बचपन में लगी चोट के कारण बाइलेटरल टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट एंकिलोसिस से पीड़ित था। इस बीमारी के कारण उसके जबड़े की वृद्धि रुक गई थी और वह वर्षों से केवल तरल आहार ही ले पाता था। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से वह कुपोषण और शारीरिक दुर्बलता का भी शिकार हो गया था। निजी अस्पतालों में उपचार का अनुमानित खर्च 3 लाख रुपये से अधिक होने के कारण वह इलाज नहीं करा सका। बाद में सिम्स पहुंचने पर उसे आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा मिली। दंत चिकित्सा विभाग में मरीज की विस्तृत जांच, रक्त परीक्षण, सीबीसीटी एवं अन्य रेडियोलॉजिकल जांच के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई।

अमलीपदर की रथयात्रा आस्था और संस्कृति की अमूल्य धरोहर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व माता सुभद्रा की पूजा-अचर्ना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

अमलीपदर की ऐतिहासिक रथयात्रा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान श्री जगन्नाथ सबको साथ लेकर चलने और लोककल्याण का संदेश देते हैं। महाप्रभु का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे, यही उनकी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले के अमलीपदर में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा महापर्व को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए और भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा की विधिवत पूजा-अचर्ना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए।

बिजली बिल समाधान योजना की अवधि सितंबर तक बढ़ी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अंतिम तिथि, जो जून माह तक निर्धारित थी, उसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन माह बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और उन्हें

राहत प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित की जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत आधारशिला है और राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कारर्वाई सुनिश्चित की जा रही है तथा वे स्वयं प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 42 हजार से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है, जो सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

बाल्टीजोर नाले पर बनेगा पुल

क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाल्टीजोर नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र के लोगों को वर्षभर सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।

रथयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना काफिला रोककर सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके आग्रह पर बच्चों के साथ आत्मीयता से सेल्फी भी खिंचवाई। रथयात्रा महापर्व में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों, भक्ति संगीत और जयघोषों के बीच पूरा अमलीपदर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। कार्यक्रम में कलेक्टर बीएस उईके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

क्लोरीनेशन अभियान से सुरक्षित पेयजल, बीमारी का खतरा हुआ कम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

किसी भी गांव के स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की नींव स्वच्छ पेयजल से ही पड़ती है। जब लोगों को शुद्ध और संक्रमणमुक्त पानी मिलता है, तो न केवल बीमारियों पर अंकुश लगता है, बल्कि पूरे गांव का जीवन स्तर भी बेहतर होता है।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रांपा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का क्लोरीनेशन अभियान इसी बदलाव की मिसाल बनकर सामने आया है। विभाग की पहल से अब गांव के हैंडपंपों और सोलर जल स्रोतों से मिलने वाला पानी अधिक सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त हो गया है। इससे जलजनित बीमारियों की आशंका में उल्लेखनीय कमी आई है और ग्रामीणों का भरोसा स्वच्छ पेयजल पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तकनीकी टीम और हैंडपंप टेक्निशियनों ने ग्राम रांपा के सभी प्रमुख जल स्रोतों का निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लोरीनेशन किया। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण किया गया, जिससे पेयजल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड और अन्य जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। क्लोरीनेशन अभियान के बाद अब ग्रामीण निश्चिंत होकर हैंडपंप और सोलर जल स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं।

गांव के लोगों का कहना है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। साथ ही इस अभियान ने उन्हें जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने, जल संरक्षण करने और सुरक्षित पेयजल के महत्व के प्रति भी अधिक जागरूक बनाया है। ग्रामीणों ने भविष्य में भी जल स्रोतों की साफ-सफाई बनाए रखने और उनका जिम्मेदारी से उपयोग करने का संकल्प लिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के तहत जिलेभर में नियमित रूप से क्लोरीनेशन अभियान संचालित कर रहा है। विभाग का उद्देश्य केवल पेयजल को शुद्ध करना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना भी है।

राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों का किया गया सम्मान

32 पदकों से चमके खिलाड़ी, सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया उत्साहवर्धन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कोरबा

उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कोरबा में डीडीएम रोड स्थित सीएमए किकबॉक्सिंग एकेडमी में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं हनुमान चालीसा भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सीएमए किकबॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल 32 पदक जीतकर कोरबा एवं छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र जो खेलेगा, वो खिलेगा आज देशभर के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में बस्तर ओलंपिक, खेल अलंकरण समारोह, उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार तथा पहली बार सरगुजा ओलंपिक जैसी पहलें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में खेलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में शीघ्र ही हॉकी लीग का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ कर रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से देश और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

रोशन करने का आह्वान करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतना खिलाड़ियों की प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिचायक है। किकबॉक्सिंग एक चुनौतीपूर्ण खेल है और इसमें सफलता प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास केवल खेल तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़े रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से खिलाड़ियों को हनुमान चालीसा भेंट की गई है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने माता-पिता, जिले और प्रदेश का नाम निरंतर रोशन करने का आह्वान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस दौरान महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष नौशाद खान, जनप्रतिनिधिगण, पार्षद, किकबॉक्सिंग समिति के पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे।

चंद्रपुर में माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्तमंत्री ओपी चौधरी

माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम का हुआ भूमिपूजन, क्षेत्र को मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का दिलाया भरोसा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-सक्ती

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित चन्द्रहासिनी विद्यापीठ परिसर में माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम का विधिवत भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह बहुउद्देशीय चिकित्सालय क्षेत्रवासियों को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में जनसेवा का सशक्त केंद्र बनेगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गोपाल जी महाप्रभु एवं माँ चन्द्रहासिनी देवी मंदिर सार्वजनिक न्यास द्वारा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के माध्यम से संचालित सीबीएसई विद्यालय ने क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है और अब आरोग्य धाम की स्थापना समाजसेवा के इस अभियान को नई ऊँचाई देगी। उन्होंने ट्रस्ट के संरक्षक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल,

अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल तथा सभी न्यासियों को इस जनहितकारी पहल के लिए बधाई दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि चंद्रपुर माँ चन्द्रहासिनी शक्तिपीठ के कारण पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस पवित्र भूमि से उनका वर्षों पुराना आत्मीय संबंध रहा है और प्रशासनिक सेवा के दौरान भी उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अस्पताल, विद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े किसी भी विकास कार्य में यदि शासन अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई औपचारिक बाधा आती है तो राज्य

सरकार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अस्पताल प्रारंभ होते ही उसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी कराई जाएगी, ताकि आसपास के ग्रामीण आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क एवं बेहतर उपचार का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल के विकास और आवश्यक सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने चन्द्रहासिनी महोत्सव को व्यापक पहचान दिलाने के लिए भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। साथ ही विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की यूपीएससी कोचिंग सहायता योजना की जानकारी दी और युवाओं से इसका अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि समाज और शासन के साझा प्रयासों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, सेवा भाव और जनकल्याण का आदर्श केंद्र बनेगा। इस अवसर पर चन्द्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट, चंद्रपुर के संरक्षक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक रामकुमार यादव, ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधिगण, ट्रस्ट के पदाधिकारी, अधिकारी-कमर्चारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

संपादकीय

विपक्ष में राहुल के लिए चुनौती बस केजरीवाल हैं

देश की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा खत्म होने के बाद कांग्रेस व राज्यों के क्षेत्रीय दलों के बीच अजब रिश्ता है। वह एकजुट भी होना चाहते हैं और आपस मे लड़ते भी रहते हैं। उनका लक्ष्य पीएम मोदी व भाजपा को केंद्र व राज्यों में हराना भी है और राज्यों में खुद को मजबूत भी करना है ।जब कांग्रेस केंद्र व राज्यों में मजबूत हुआ करती थी तो क्षेत्रीय दल व नेता कमजोर हुआ करते थे ।केंद्र व राज्यों मे कांग्रेस कमजोर हुई तो क्षेत्रीय दल मजबूत हुए,क्षेत्रीय दलों के नेता मजबूत हुए। वह राष्ट्रीय नेता के तौर पर जाने जाने लगे। यानी उनका संबंध ऐसा है कि एक मजबूत होगा तो दूसरे का कमजोर होना जरूरी है। एक कमजोर होगा तो दूसरे का मजबूत होना जरूरी है ।हाल के चुनाव में बिहार व बंगाल में क्षेत्रीय दलों के हारने से राज्यों में भाजपा तो मजबूत हुई है। क्षेत्रीय दल कमजोर हुए और मजे की बात है माना जा रहा है कि पं .बंगाल में अब कांग्रेस मजबूत हो सकती है, वह टीएमसी की जगह ले सकती है और आने वालों दिनों में विपक्ष की भूमिका में आ सकती है।

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए विपक्ष के कई नेता चुनौती बने रहे हैं। उनके कारण वह विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में नही उभर सके हैं,अपनी बात क्षेत्रीय दलों से मनवा नहीं पाते थे ।कभी शरद पवार उनके विरोध में खड़े हो जाते थे,कभी ममता उनके विरोध में सामने आ जाती थी। बिहार में लालू परिवार उनके रास्ते में आ जाता था ।यूपी मे अखिलेश कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। बिहार, बंगाल में भाजपा की जीत, महाराष्ट्र मे शरद पवार व उध्दव ठाकरे की पार्टी टूटने, बंगाल में ममता के कमजोर होने का लाभ कांग्रेस और राहुल गांधी को यह हुआ है कि विपक्ष में उनको चुनौती देने वाले नेताओं की संख्या कम होती गई है ।केरल व तमिलनाडु में चुनाव के बाद कांग्रेस राजनीतिक रूप से मजबूत हुई है। राहुल गांधी अब विपक्ष के सबसे मजबूत व बड़े नेता हैं। उनके सामने अब विपक्ष में कोई मजबूत नेता है तो वह अरविंद केजरीवाल हैं। यानी राहुल गांधी को देश की राजनीति, पंजाब सहित कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल ही चुनौती दे सकते हैं।

सीजेपी आंदोलन के चलते हुए युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने के लिए राहुल गांधी व केजरीवाल के बीच होड़ सी लगी हुई है कि युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। सीजेपी के आंदोलन को विपक्ष के बड़े नेताओं मे सबसे पहले समर्थन देने केजरीवाल जंतरमंतर पहुंचे थे। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आतिशी मारलेना आदि नेता भी पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे राजनीतिक दल पहुंचे और सबसे आखिरी में कांग्रेस ने पवन खेड़ा जैसे नेता को भेजकर समर्थन करने की औपचारिकता पूरी की थी। इससे ऐसा लग रहा था कि पेपरलीक,शिक्षामंत्री के इस्तीफे को लेकर एक ही आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता भी जंतर मंतर के आकर आंदोलन में शामिल होंगे। सीजेपी के संसद मार्च, पुलिस के लाठी चार्ज के बाद राहुल गांधी व केजरीवाल के बीच युवाओं के बीच जगह बनाने को लेकर फिर से नई होड़ शुरू हो गई। केजरीवाल ने लाठीचार्ज की निंदा की, घायलों के इलाज व लीगल सहायता की घोषणा की, अस्पताल घायल युवाओं को देखने गए तो राहुलगांधी ने पीएम आवास के पास धरना दिया, घायलों को देखने अस्पताल भी गए और साफ कर दिया उनका युवाओं के लिए आंदोलन सीजेपी के आंदोलन से अलग है।

अब सीजेपी सरकार से अलग मांग कर रही है और कांग्रेस सरकार से अलग मांग कर रही है। ऐसे मे केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह युवाओं के आंदोलन को कमजोर कर रही है और वह भाजपा व मोदी से मिली हुई है। सीजेपी भी शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस भी शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस मामले में वह आप से आगे रह सके। सीजेपी आप वाले माने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन का लाभ केजरीवाल को होगा। वह देश में युवाओं के मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। राहुल गांधी यही नहीं चाहते हैं कि विपक्ष मे उनके लिए जो बड़ी चुनौती केजरीवाल है, वह और बड़ी चुनौती बने। केजरीवाल को और बड़ी चुनौती न बनने देने के लिए जरूरी है कि पंजाब में केजरीवाल की हार हो। जैसे यूपी मे अखिलेश,बिहार में तेजस्वी और बंगाल में ममता की हार बाद उनका राजनीतिक कद कम हुआ है, उसी तरह केजरीवाल यदि पंजाब में हारते है तो उनका राजनीतिक कद दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह कम हो जाएगा और राहुल गांधी का कद विपक्ष के तमाम नेताओं की तुलना में बढ़ जाएगा। तब वह विपक्ष की तरफ से पीएम पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाएँगे।

राहुल गांधी को युवाओं के मजबूत नेता के रूप में पेश करने के लिए पीएम आवास के सामने धरना दिया गया है, मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी उसे सीजेपी के रास्ते पर चलना पड़ रहा है। केंद्र की सत्ता चलाने का लंबा अनुभव रखने वाली कांग्रेस संसद के बजाय सड़क पर उतर अपनी बात रख रही है तो इससे साफ हो जाता है कि वह चाहती क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। लोकतंत्र में सड़क की राजनीति भी होती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी संसद की जगह सड़क को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, अब दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि मौका है तो इसका लाभ क्यों न उठाया जाए ।केजरीवाल सड़क की राजनीति करते हैं, उनको मात सड़क की राजनीति करके दिया जा सकता है ।दिल्ली में तीन बार और एक बार पंजाब मे कांग्रेस को हराकर केजरीवाल राहुल गांधी से बड़े नेता तो हैं, राहुल गांधी उनको पंजाब चुनाव में हराकर खुद को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं और अपने रास्ते की एक और बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं।

युवा आक्रोश : चुनौती नहीं, चेतावनी..प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ा प्रश्न

शैलजा सिंह गाजियाबाद

इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र का भविष्य संसद की बहसों से कम और उसके विद्यार्थियों की आँखों से अधिक पढ़ा जाता है। जब विश्वविद्यालयों की कक्षाओं से निकलकर छात्र जंतर-मंतर तक पहुँचते हैं, तब लोकतंत्र के सामने केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक प्रश्न खड़ा होता है—क्या व्यवस्था अपने भविष्य की आवाज सुनने को तैयार है? आज भारत विश्व का सबसे युवा देश बनने की ओर अग्रसर है। यह जनसंख्या केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूँजी है। यदि यही युवा आशा से भरा होगा तो भारत विश्व का नेतृत्व करेगा; यदि यही युवा निराश होगा, तो विकास की सबसे ऊँची इमारत भी भीतर से खोखली रह जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। यही कारण है कि जब छात्र शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार, पारदर्शिता या भविष्य से जुड़े प्रश्नों को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं, तब यह केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं रह जाती; यह स्वयं प्रधानमंत्री के नेतृत्व की नैतिक परीक्षा बन जाती है।

जंतर-मंतर लोकतंत्र की वह जगह है जहाँ नारों से अधिक उम्मीदें खड़ी होती हैं। वहाँ पहुँचा प्रत्येक छात्र सरकार का विरोधी नहीं होता; वह अपने सपनों का प्रतिनिधि होता है। उसकी आवाज में व्यवस्था को गिराने की इच्छा नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुनने की अपेक्षा भी हो सकती है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहली प्रतिक्रिया संवाद होनी चाहिए, टकराव नहीं; विश्वास होना चाहिए, अविश्वास नहीं।

विश्व के विकसित देशों ने इसी सिद्धांत को अपनाया। फि नलैंड ने शिक्षा व्यवस्था में ऐसा विश्वास बनाया कि छात्र सरकार के साझेदार बने। जर्मनी ने कौशल, उद्योग और शिक्षा को जोड़कर युवाओं को अवसर दिए। दक्षिण कोरिया ने युद्ध और गरीबी से निकलकर शिक्षा तथा अनुसंधान को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। जापान ने अपने युवाओं को अनुशासन, तकनीक और नवाचार से जोड़ा। इन देशों ने यह समझ लिया कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी सेना जितनी ही उसकी शिक्षा व्यवस्था भी होती है।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकसित राष्ट्र केवल आर्थिक आँकड़ों से नहीं बनते। विकसित राष्ट्र तब बनते हैं जब सरकार अपने सबसे छोटे नागरिक की चिंता को भी राष्ट्रीय प्रश्न मानती है। यदि छात्रों का विश्वास डगमगा जाए तो विकास की गति भी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आंदोलन कितने दिनों तक चलता है; बल्कि यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं जिनमें देश का भविष्य सड़क पर खड़ा होकर उत्तर माँगता है। यही किसी भी लोकतांत्रिक नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा है।

किसी भी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की वास्तविक पहचान तब नहीं होती जब चारों ओर प्रशंसा हो; उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब असहमति सामने खड़ी हो। जंतरझमंतर पर खड़े छात्र केवल भीड़ नहीं होते, वे उस पीढ़ी का प्रतीक होते हैं जो अपने भविष्य के बारे में उत्तर चाहती है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और लोकतांत्रिक नेतृत्व की चुनौती भी होती है।

यदि छात्र शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं, छात्रवृत्ति, रोजगार या अन्य सार्वजनिक नीतियों से जुड़े प्रश्न उठा रहे हों, तो एक दूरदर्शी नेतृत्व का पहला कदम संवाद होना चाहिए। प्रतिनिधियों से बातचीत, तथ्यों की निष्पक्ष समीक्षा, समयबद्ध जाँच (जहाँ आवश्यक हो), स्पष्ट सार्वजनिक संचार और दीर्घकालिक सुधार.... ये ऐसे उपाय हैं जो विश्वास बहाल कर सकते हैं। नेतृत्व की शक्ति केवल निर्णय लेने में नहीं, बल्कि यह दिखाने में भी होती है कि निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया से लिए जा रहे हैं।

दुनिया के कई विकसित देशों ने यही रास्ता अपनाया। स्वीडन और नॉर्वे में सार्वजनिक संस्थाओं पर भरोसा इसलिए बना क्योंकि सरकारों ने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक संवाद को महत्व दिया। फि नलैंड ने शिक्षा को राजनीतिक विवाद से ऊपर रखकर दीघर्कालिक सुधार किए। जर्मनी ने कौशल विकास और उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी बनाई, जिससे युवाओं के लिए अवसर बढ़े। इन अनुभवों की समान सीख है कि स्थायी विकास केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं और नागरिक विश्वास से आता है।

भारत की परिस्थितियाँ इन देशों से भिन्न हैं....जनसंख्या अधिक है, विविधता व्यापक है और चुनौतियाँ भी अलग हैं। इसलिए समाधान भी भारत की संवैधानिक व्यवस्था, संघीय ढाँचे और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप ही होंगे। फिर भी एक सिद्धांत सावभौमिक है: जब युवाओं को यह भरोसा हो कि उनकी बात सुनी जाएगी और समस्याओं पर निष्पक्षता से विचार होगा, तब लोकतंत्र अधिक सशक्त होता है।

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो भौतिक अवसंरचना के साथ-साथ संस्थागत विश्वास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और युवाओं की भागीदारी को भी उतना ही महत्व देना होगा। यही वे आधार हैं जिन पर विकसित राष्ट्र अपनी दीघर्कालिक सफलता खड़ी करते हैं।

समाहार

प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल नई परियोजनाएँ शुरू करना नहीं होगी; बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ किसी छात्र को यह महसूस न हो कि उसकी बात सुनाने का एकमात्र रास्ता सड़क है। उसी प्रकार, लोकतंत्र की शक्ति भी इस बात में है कि नागरिक अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से रखें।

जब सरकार सुनती है, संस्थाएँ निष्पक्षता से काम करती हैं और नागरिक जिम्मेदारी के साथ भाग लेते हैं, तब केवल एक आंदोलन समाप्त नहीं होता—विश्वास मजबूत होता है। और अंततः किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वहाँ भविष्य और नेतृत्व आमने-सामने नहीं, बल्कि एक ही दिशा में साथ-साथ चलते हैं।

सीड बॉल अभियान- हरियाली बढ़ाने का सरल और प्रभावी माध्यम

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, अशोक कुमार चंद्रवंशी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर

सीड बॉल पर्यावरण को हरा-भरा बनाने और वनीकरण (रिफॉरेस्टेशन) का एक बेहद सरल, किफायती और अत्यधिक प्रभावी माध्यम है। इसमें बीजों को मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियों के रूप में सुरक्षित कर दिया जाता है, जिससे वे बिना मेहनत के दुर्गम स्थानों पर भी उग जाते हैं। सीड बॉल- बीज, मिट्टी (मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी) और जैविक खाद (गोबर या वर्मीकम्पोस्ट) का एक छोटा और सूखा गोला होता है। बीजों को इस प्राकृतिक आवरण में लपेटकर सुखा लिया जाता है। मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तब सीड बॉल्स का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इन्हें यात्रा करते समय या खाली जगहों पर पैदल चलते हुए मिट्टी पर बिखेर दें। पानी के संपर्क में आते ही ये पौधे के रूप में विकसित होना शुरू हो जाती हैं। बारिश का मौसम पौधारोपण और वनों के विस्तार के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इसी उद्देश्य से वन विभाग द्वारा सीड बॉल (बीज गोला) अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने का प्रभावी प्रयास है, जहाँ पौधारोपण करना कठिन होता है।

क्या है सीड बॉल?

सीड बॉल मिट्टी, गोबर या जैविक खाद और विभिन्न वृक्षों के बीजों से तैयार किया गया छोटा गोलाकार गोला होता है। इसे जंगलों, पहाड़ियों, खाली भूमि और दुर्गम क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। वर्षा का पानी मिलने पर बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेते हैं।

वन विभाग का हरित अभियान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम, वन महोत्सव तथा युवा फॉर नेचर जैसे अभियानों के साथ सीड बॉल कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। स्कूलों, महाविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से हजारों-लाखों सीड बॉल तैयार कर जंगलों और खाली भूमि में डाली जा रही हैं।

जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका

सीड बॉल में महुआ, इमली, हर्रा, बहेड़ा, जामुन, करंज, नीम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, शाल, बीजा, चार, खमार सहित स्थानीय प्रजातियों के बीजों का उपयोग किया

जाता है। इससे प्राकृतिक वनों का विस्तार होता है, वन्यजीवों को भोजन और आश्रय मिलता है तथा जैव विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम

सीड बॉल अभियान से हरित आवरण बढ़ने के साथ-साथ जल संरक्षण, मिट्टी के क्षरण या कटाव में कमी, कार्बन अवशोषण तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी सहायता मिलती है। यह कम लागत में अधिक क्षेत्र को हरित बनाने का प्रभावी उपाय है।

जनभागीदारी से बनेगा हरित भविष्य

वन विभाग का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है। जब बच्चे, युवा, महिलाएं और ग्रामीण इस अभियान से जुड़ते हैं, तो हर व्यक्ति प्रकृति संरक्षण का सहभागी बनता है।

हर नागरिक निभाए अपनी जिम्मेदारी

यदि प्रत्येक नागरिक वर्षा ऋतु में कुछ सीड बॉल तैयार कर उपयुक्त स्थानों पर डाले या पौधारोपण में भागीदारी करे, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ का हरित क्षेत्र और अधिक समृद्ध होगा। सीड बॉल अभियान प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है।

स्वस्थ पशुधन, समृद्ध किसान : मुंगेली में 582 शिविरों से बदली पशुपालन की तस्वीर

मुंगेली जिले में पशुधन संरक्षण, उन्नत नस्ल विकास एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, रोग नियंत्रण एवं गांव-गांव आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जिले में पशुपालन को नई दिशा मिली है। इन प्रयासों से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ दुग्ध उत्पादन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

> 07 लाख 67 हजार से अधिक पशुओं का हुआ टीकाकरण

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. आर.एम. त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 67 हजार 257 पशुओं का उपचार किया गया। वहीं एक लाख 22 हजार 804 पशुओं को औषधियों का वितरण, 93 हजार 561 पशुओं को कृमिनाशक दवा तथा एक लाख 09 हजार 84 पशुओं को किलनी मुक्त करने के लिए डिटिकिंग की गई। पशु स्वास्थ्य सेवाओं के इस व्यापक अभियान से हजारों पशुपालकों को सीधा लाभ मिला। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 09 हजार 978 निकृष्ट सांडों का बंधियाकरण किया गया। साथ ही 20 हजार 341 गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 05 हजार 685 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। इनमें 02 हजार 900 से अधिक मादा बछियां शामिल हैं, जो भविष्य में अधिक दुग्ध उत्पादन कर पशुपालकों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगी।

छत्तीसगढ़ शासन की लिंग वर्गीकृत वीर्य योजना के तहत 123 गायों का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, जिससे 99 मादा बछियों का जन्म हुआ। यह उपलब्धि जिले में उच्च उत्पादक पशुधन तैयार करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पशुओं को संक्रामक एवं जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए जिले के 02 लाख 59 हजार 348 पशुधन में 07 लाख 67 हजार 531 प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किए गए। इनमें गलघोंटू एवं एकटंगिया, खुरहा-चपका, लम्पी स्किन डिजीज, इंटरोटॉक्सीमिया तथा पीपीआर जैसी बीमारियों से बचाव के टीके शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए 881 बछियों का टीकाकरण तथा 04 हजार 63 पशुओं को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। पशु रोगों की समय पर पहचान के लिए रक्त, गोबर, ट्यूबरक्लोसिस एवं जॉन्सडिसीज सहित विभिन्न प्रयोगशाला जांच भी नियमित रूप से की गईं। पशुपालकों को घर के समीप बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 582 बहुउद्देशीय पशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशन, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ वैज्ञानिक पशुपालन एवं आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ी और किसानों को बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिला है।

भारत में कमजोर होती लोकतंत्र की जड़ें और सिसकती संसदीय व्यवस्था

राजीव चौबे, फाउंडर - राष्ट्रीय चेतना न्यूज

नीट पेपर लीक के बाद देश के 30 युवाओं की आत्महत्या की खबर आई और देखते ही देखते राजधानी की सियासत उस लाश पर टूट पड़ने वाले चील-गिद्धों जैसी हो गई। जिस त्रासदी पर पूरे देश को शोक में होना चाहिए था, उसी पर सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी फसल काटने निकल पड़े। पिछले दो दिनों का घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत का लोकतंत्र जड़ से कमजोर हो रहा है और संसद अपनी गरिमा खोकर सड़क में तब्दील हो रही है।

आंदोलन या अराजकता की पटकथा?

नीट पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन जायज था। छात्रों की नाराजगी स्वाभाविक थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को दिशा दी गई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए।

आयोजकों ने वीडियो संदेश में प्रदर्शनकारियों से डंडे और मिर्च पाउडर लेकर आने का आह्वान किया। "नेपाल और बांग्लादेश बना देना" जैसी भाषा बोली गई। 13 मई को एक वरिष्ठ नेता ने खुले मंच से कहा था कि जिस तरह पड़ोसी देशों में युवा आंदोलन से तख्ता पलट हुआ, वैसा यहां क्यों नहीं हो सकता? ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या कुछ ताकतें विदेशी फंडिंग और विदेशी एजेंडे

के साथ मिलकर इस देश की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में हैं? जब आंदोलन का मकसद संवाद नहीं, बल्कि टकराव बन जाए तो वह आंदोलन नहीं रहता।

जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ, फिर आमरण अनशन आया। जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस पर भी विपक्ष को सदमा लगा, मानो उन्हें किसी शहादत का इंतजार था। बोया कुछ नहीं, पर फसल काटने की होड़ मच गई।

संसद ठप्प, सड़क पर तमाशा

20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। आज तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर किस लिए भेजती है? प्रश्न पूछने के लिए, बहस करने के लिए, कानून बनाने के लिए। लेकिन एक साल में 60-70 दिन चलने वाले सत्र के 20-25 दिन हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं।

दो दिन संसद ठप्प करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। 21 तारीख को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर गए। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाके में जब पुलिस ने रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। क्या देश के कानून बनाने वाले ही जब कानून तोड़ेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए? प्रशासन ने समझाया, लेकिन बात न मानने पर गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजना पड़ा। रात 10 बजे रिहा भी कर दिया गया।

20 तारीख को संसद मार्च के दौरान भी भीड़ बेकाबू होकर पुलिस पर पथराव करने लगी थी। यदि 21 को भी भीड़ प्रधानमंत्री निवास में घुस जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अराजकता का नहीं।

लाशों पर राजनीति

सबसे शमर्नाक पहलू यह है कि उन 30 मासूमों की मौत पर भी सियासी दलों में "अधिकार" की लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी ने आंदोलन हाईजैक किया। आप कह रही है श्रेय कांग्रेस ले गई। विपक्ष लगातार "बर्बर लाठीचार्ज" का आरोप लगा रहा है, लेकिन उन्हीं भीड़ में शामिल कुछ लोगों द्वारा पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर किए जा रहे हमलों पर मौन है।

यह भी समझना होगा कि नीट परीक्षार्थी की उम्र अधिकतम 18-20 साल होती है। 6 जून से 21 जुलाई तक जंतर-मंतर पर दिखने वाली भीड़ में अधिकांश चेहरे वो थे जो पहले शाहीन बाग, किसान आंदोलन, जेएनयू, जामिया में भी दिखे थे। प्रश्न उठता है: क्या यह छात्रों का आंदोलन है या पेशेवर आंदोलनकारियों का मंच?

सत्ता पक्ष की निष्क्रियता भी जिम्मेदार

आलोचना केवल विपक्ष की नहीं, सत्ता की भी होनी चाहिए। "पार्टी विद डिफरेंस" कहने वाली भाजपा कल तक इस मुद्दे पर संवेदनहीन दिखी। आज जब दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर दी।

लेकिन यह कदम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। 30 आत्महत्याओं के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा, आरोपियों पर बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट - ये सब पहले होना चाहिए था। मंत्री का इस्तीफा हर समस्या का हल नहीं है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना भी सरकार चलाने का तरीका नहीं है। युवा वर्ग आज बेरोजगारी और पेपर लीक दोनों से आहत है। उनके जख्मों पर सहानुभूति का मरहम नहीं लगा तो आने वाले चुनाव में काले झंडे तय हैं।

संवाद की जरूरत

आज देश को टकराव नहीं, संवाद चाहिए। विपक्ष को समझना होगा कि संसद विरोध के लिए नहीं, समाधान के लिए है। सरकार को समझना होगा कि युवा केवल नारे नहीं, रोजगार और पारदर्शिता चाहते हैं।

इतिहास गवाह है कि आंदोलन से जन्मे दल - जनता पार्टी, जनता दल, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट - तात्कालिक लक्ष्य के साथ आए और सिद्धांतों के अभाव में विलुप्त हो गए। वहीं नीति और सिद्धांत पर चलने वाले दल ही दीर्घायु हुए।

यदि सीजेपी जैसे संगठन इस आंदोलन को सत्ता का सीढ़ी मान रहे हैं, तो देश के युवाओं को सोचना होगा। गुस्सा जायज है, लेकिन गुस्से की कमान ऐसे हाथों में न जाए जो उसे देश के खिलाफ इस्तेमाल करें। लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब संसद सिसकना बंद करेगी और सड़क पर संवाद शुरू होगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सामने सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा।

ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की घटती मौजूदगी

अध्ययन के दौरान 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण हुआ। उससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी घटती चली गई है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट का सार है कि ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था नाकाम होने के कगार पर है। रिपोर्ट- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभाओं में निम्न भागीदारी- शीर्षक से जारी हुई है। कहा गया है कि यह अध्ययन स्थानीय स्व-शासन पर देश के सबसे बड़े जमीनी आकलनों में से एक है। इसके तहत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण किया गया। इससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी लगातार घटती चली गई है। आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि बैठकों में शामिल न होने की वजह रोजगार और कमाई से जुड़ी हैं। कामकाजी वर्ग के लिए काम-धंधा छोड़कर बैठक में आना कठिन होता है।

फिर बैठकों में स्थानीय रसूखदार लोगों का ही दबदबा बना रहता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि ग्राम सभाएं स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में लगभग 13 प्रतिशत समय लगाती हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के उपायों पर केवल चार फीसदी समय खर्च करती हैं। चूंकि केंद्रीय अनुदान से मिलने वाला पैसा काफी हद तक पहले से तय केंद्रीय प्राथमिकताओं (जैसे जल जीवन मिशन) से जुड़ा होता है, इसलिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजना पर अमल लगभग नामुमकिन ही बना रहता है। इस रूप में पंचायती राज संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसी बन कर रह गई हैं। जबकि 73वें और 74वें संविधान में परिकल्पना उन्हें शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित करने की गई थी।

वैसे, यह आरंभ में ही स्पष्ट हो गया था कि पंचायती संस्थाओं के लिए वित्त आयोग से तय अपना बजट और अपनी नौकरशाही नहीं होगी, तो उनका यही हाल होगा। फिर भी इस ओर कोई पहल नहीं हुई। इस सिलसिले में अक्सर उल्लेख होता है कि अमेरिका जैसी पूंजीवादी और चीन जैसी समाजवादी व्यवस्थाओं में एकमात्र समानता शासन का कारगर विकेंद्रीकरण है। दोनों जगहों पर इस नीति के सकारात्मक परिणाम जग-जाहिर हैं। मगर भारत में केंद्र हो या राज्य, अपने अधिकार क्षेत्र में कटौती के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा, ताजा रिपोर्ट में शामिल विलाप है।

दुर्ग शहर में छात्रों के समर्थन में पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन

नयापारा से बघेरा चौक तक निकाली रैली, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की निंदा, कांग्रेस पार्टी युवाओं और छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान और जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के निर्देश पर पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया।

पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार के नेतृत्व में कांग्रेसजन नयापारा चौक में एकत्रित हुए। इसके बाद जंतर-मंतर, नई दिल्ली में युवाओं और छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं और छात्रों की गिरफ्तारी तथा उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बघेरा चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों और विपक्ष के नेताओं पर लाठीचार्ज एवं गिरफ्तारी लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस दमनात्मक रवैये की कड़ी निंदा करती है और छात्रों की आवाज को दबाने के हर प्रयास का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती रहेगी।"

पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार ने कहा कि "देश का युवा अपने भविष्य, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उनकी आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी युवाओं और छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।"

प्रदर्शन में राजेश यादव, रायसिंह डिकोला, प्रेमलता साहू, पोषण साहू, विजयंत पटेल, कौशल किशोर सिंह, जमुना साहू, नासिर खोखर, निकिता मिलिंद, गुरदीप सिंह भाटिया, एजाज खान, विनोद साहू, धनवंती निषाद, सुनीत घोष, शिशिरकांत कसार, ब्रिजलाल पटेल, लिखन साहू, अनिल देवांगन, नंदकिशोर शर्मा, प्रीतम देशमुख, बृजमोहन तिवारी, दुष्यंत देवांगन, देव सिंहा, मुकेश साहू, विजेंद्र भारद्वाज, अनीस रजा, चिराग शर्मा, इसाक अली, गौरव सेन, हरीश सिन्हा, जगदीश कसार, मनीष सोनवानी, हिमांशु सिंहां, चैतन्य बंछोर, सुरेश जंघेल, जय साहू, विष्णु निषाद, हिमांशु शर्मा, तोरण निषाद, टी.आर. वर्मा, भीमा चौहान, मनीष सिंहां, अरुण यादव, यस मानिकपुरी, आयुष शर्मा, अमित मिश्रा, छबिलाल साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

खास खबर

छग के लिए स्वर्णिम दिन, मास्टर्स राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग में नस्कर टंडन ने जीते 3 स्वर्ण

नई दृष्टिबिंदु / संभाजीनगर

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 18 से 23 जुलाई तक आयोजित मास्टर्स राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया।

93 किलोग्राम भार वर्ग में नस्कर टंडन ने तीनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर दिन को स्वर्णिम बना दिया। नस्कर ने स्क्वाट में 102 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 82 किलोग्राम और डेडलिफ्ट में 130 किलोग्राम वजन उठाया। कुल 315 किलोग्राम के साथ उन्होंने क्लीन स्वीप किया। इसी भार वर्ग में मुन्नू स्वामी ने भी दमदार प्रदर्शन किया। मुन्नू ने स्क्वाट में 100 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 75 किलोग्राम और डेडलिफ्ट में 110 किलोग्राम उठाकर कुल 285 किलोग्राम के साथ तीन रजत पदक अपने नाम किए। 105 किलोग्राम भार वर्ग में राज वासनिक ने बेंच प्रेस में 182.5 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता। स्क्वाट में 290 किलोग्राम के साथ कांस्य और डेडलिफ्ट व कुल योग में रजत पदक हासिल कर उन्होंने छत्तीसगढ़ का पदक खाता और मजबूत किया।

पहले ही दिन खुला था खाता : प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही छत्तीसगढ़ ने पदक जीतने शुरू कर दिए थे। 66 किलोग्राम भार वर्ग में अखिलेश पांडेय ने ओवरऑल स्पर्धा में पदक जीता था। वहीं 93 किलोग्राम मास्टर्स क्लासिक पावरलिफ्टिंग में मुन्नू स्वामी ने डेडलिफ्ट में कांस्य पदक हासिल किया था।

एसोसिएशन ने दी बधाई : छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक जी. सुरेश बाबे, संरक्षक इंद्रजीत सिंह 'छोटू', अध्यक्ष कैलाश जैन बरमेचा, महासचिव कृष्णा साहू, कायर्कारी अध्यक्ष तुलसी सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवन कुमार जैन और राजेंद्र सिंह यादव सहित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने अखिलेश पांडेय, नस्कर टंडन, मुन्नू स्वामी और राज वासनिक को राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

निगम आयुक्त ने किया जोन-1, 2 और 3 का निरीक्षण जलभराव, पेयजल व सफाई व्यवस्था सुधारने निर्देश

डूबान क्षेत्र, पानी टंकी और तालाब का किया अवलोकन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने मंगलवार को निगम क्षेत्र के विभिन्न जोनों का निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जलभराव, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

नालियों की नियमित सफाई हो

आयुक्त ने सबसे पहले जोन-1 नेहरू नगर स्थित बाम्बे आवास के पास डूबान क्षेत्र का निरीक्षण किया। बरसात में यहां जलभराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने नालियों की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। कहा कि नालियों में कचरा और गाद जमा न हो और जलभराव वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो।

गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

इसके बाद जोन-2 रामनगर स्थित नवीन पानी टंकी का निरीक्षण किया। टंकी की स्थिति और संचालन व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आयुक्त ने संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा, जिससे क्षेत्रवासियों को नियमित और सुचारू पेयजल मिल सके। निरीक्षण के अंतिम चरण में जोन-3 दुर्गापारा स्थित तालाब का जायजा लिया। उन्होंने तालाब और आसपास साफ-सफाई व्यवस्था देखी और नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि तालाब के आसपास गंदगी और कचरा जमा न होने दिया जाए। जो भी नागरिक तालाब किनारे कचरा फेंकते पाए जाएं, उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, अनिल सिंह, अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, नितेश मेश्राम, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, शंकर सुमन मरकाम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, बीरेन्द्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, चुड़ामणी यादव सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार 8 माह की गर्भवती हुई युवती

नई दृष्टिबिंदु / बागनदी

थाना बागनदी पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में आरोपी को रिपोर्ट दर्ज होने के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता ने 23 जुलाई को परिजनों के साथ थाना बागनदी पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उसने बताया कि आरोपी खुमेन्द्र कुमार श्याम उर्फ कुणाल श्याम, पिता परदेशी श्याम, उम्र 21 वर्ष, निवासी सड़क चिरचारी ने शादी का वादा कर लगातार शारीरिक शोषण किया। इसके कारण वह 8 माह की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत पर थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 21/2026 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की गई। अपराध दर्ज होने के महज 3 घंटे के अंदर आरोपी खुमेन्द्र कुमार श्याम उर्फ कुणाल श्याम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, उप निरीक्षक देवादास भारती, आरक्षक अनिल टोण्डे और आरक्षक टाकेश्वर पटेल की भूमिका सराहनीय रही।

महापौर अलका बाघमार ने नाली निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आज वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर, मालवीय नगर तथा वार्ड क्रमांक 16 सिकोला भाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन नाली कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता, तकनीकी मानकों एवं जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म विभाग के प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य निलेश अग्रवाल, पार्षद मनोज सोनी, उप अभियंता पंकज साहू, सिद्धार्थ साहू, उप अभियंता अपर्णा मिश्रा सहित निगम के अधिकारी एवं कमर्चारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नाली निर्माण कार्य स्वीकृत डीपीआर, स्वीकृत ड्राइंग एवं निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि नालियों में निर्धारित डिजाइन के अनुसार पर्याप्त एवं समान ढाल (ग्रेडिएंट) सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षा एवं अपशिष्ट जल का निर्बाध प्रवाह बना रहे और कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

महापौर ने कहा कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रारंभिक एवं अंतिम लेवल का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। निर्माण में उपयोग होने वाली सीमेंट, गिट्टी, रेत सहित सभी सामग्री निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप हो तथा नाली के जॉइंट्स, फिनिशिंग एवं सतह को मजबूत एवं समतल बनाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क, पेयजल पाइपलाइन, विद्युत पोल एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे तथा निकलने वाले मलबे का नियमित निष्पादन कर आवागमन सुचारु बनाए रखा जाए।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कार्य पूर्ण होने के बाद नाली में पानी प्रवाहित कर वॉटर फ्लो टेस्ट कराया जाए। परीक्षण में ढाल एवं जल निकासी संतोषजनक पाए जाने के बाद ही संबंधित कार्य का देयक तैयार किया जाए।

महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि नगरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की सवोच्च प्राथमिकता है। नाली निर्माण कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य वर्षो तक सुचारु जल निकासी सुनिश्चित करना है। गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी।

लोक कर्म विभाग के प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने कहा कि नगर निगम द्वारा सभी निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों को तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विकास कार्य पूर्ण कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कुथरेल में लगा सामुदायिक मध्यस्थता विधिक साक्षरता शिविर

"संवाद और सहमति से हों विवादों का समाधान" दिया गया संदेश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की "Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India" SOP, 2026 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ग्राम कुथरेल में सामुदायिक मध्यस्थता विषयक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के. विनोद कुजूर ने किया।

आपसी सहमति से विवाद समाधान पर जोर : शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को यह जानकारी देना था कि छोटे-बड़े सामाजिक, पारिवारिक और सामुदायिक विवादों का निपटारा केवल अदालत के जरिए ही नहीं, बल्कि आपसी संवाद, समझ और सामुदायिक मध्यस्थता से भी सम्मानजनक तरीके से किया जा सकता है। बताया गया कि सामुदायिक मध्यस्थता में किसी की हार-जीत नहीं होती। इसमें दोनों पक्षों की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करते हुए ऐसा समाधान निकाला जाता है जिसे सभी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकें।

विभिन्न विभागों ने दी जानकारी : कार्यक्रम में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशु चिकित्सा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग से बीएमओ देवेन्द्र बेलचंदन, महिला एवं बाल विकास से सुपरवाइजर ममता साहू, जनपद पंचायत से परियोजना अधिकारी गौरव मिश्रा, राजस्व से पटवारी सतीश दीवान, पशु चिकित्सा से प्रेमलता देवांगन उपस्थित रहे।

भारती लॉ कॉलेज दुर्ग के असिस्टेंट प्रोफेसर संपदा बैस, सरिता गुप्ता सहित प्राध्यापकगण और विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। विधि के छात्रों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि न्याय और सामाजिक समरसता के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थता के जरिए समाज में संवाद, सहयोग और आपसी विश्वास की भावना को मजबूत कर न्याय को आमजन तक सुलभ बनाना ही इस पहल का उद्देश्य है।

बैठक में चर्चा | भाजयुमो जिला भिलाई की प्रथम परिचयात्मक बैठक संपन्न

बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता विस्तार व निगम चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई की प्रथम परिचयात्मक बैठक जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक भाजपा जिला भिलाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने कहा कि भाजयुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में प्रत्येक बूथ तक संगठन को मजबूत करना, युवाओं को जोड़ना और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना युवा मोर्चा की सवोच्च प्राथमिकता होगी।

भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए युवा मोर्चा जिले में संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

आगामी कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प

बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों, सदस्यता विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और नगर निगम चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत मंथन हुआ। अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन हित को सवीपरि रखते हुए पूरी निष्ठा से कार्य करने, प्रत्येक मंडल और बूथ को सशक्त बनाने तथा आगामी सभी कार्यक्रमों को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया।

बैठक में भाजपा जिला प्रभारी रामजी भारती, जिला महामंत्री मनीष अग्रवाल, सुषमा जेठानी, भाजयुमो जिला प्रभारी दीक्षा अग्रवाल, सह प्रभारी मुकेश साहू, जिला महामंत्री विनय सेन, अमित राजपूत उपस्थित रहे। प्रदेश मंत्री आकाश ठाकुर, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य कुंदन फेकर, प्रदेश नीति अनुसंधान प्रमुख विशाल दीप नायर, प्रदेश आईटी सेल प्रभारी अमित मिश्रा, प्रदेश खेल एवं कला सह-प्रमुख प्रशम दत्ता, प्रदेश शासकीय योजना सह प्रमुख कुशल साहू, जिला युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आनंद ताम्रकर ने भी अपने विचार रखे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं. ..../अ-27/ वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक होमेश मिरे अन्य 1 आ./ध.प. स्व. अजय मिरे निवासी - पोला ग्राउण्ड के पास छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा ग्राम - कोहका. प.ह.नं. 4.5. रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि ख.न. 7863/1 रकबा 0.0260 हे. भूमि आवेदक एवं अनावेदक के नाम पर शमिलात खातें में दर्ज है। उपर वर्णित भूमि को खातेदारों द्वारा आपसी सहमती के अनुसार खाता विभाजन किये जाने हेतु आवेदनमय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07/08/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/7/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

नाम परिर्वतन

प्ररूप-एक

नाबालिक पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित)

मै अजित मेहता **AJIT MEHTA** (माता / पिता/पालक का नाम) पिता मटुकी मेहता गांव / शहर ग्राम व पो. रसमड़ा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ने अपने नाबालिक पुत्र अभिमन्यु **ABHIMANU** (पुराना नाम) से बदलकर अभिमन्यु मेहता **ABHIMANYU MEHTA** (नया नाम) रख लिया है।

अजित मेहता
माता/ पिता/पालक के हस्ताक्षर

फिल्म 'गनमास्टर जी9' में निगेटिव रोल में नजर आएंगे अपारशक्ति खुराना

अभिनेता अपारशक्ति खुराना जल्द ही इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'गनमास्टर जी9' में निगेटिव रोल में नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए फिल्म के सेट से पर्दे के पीछे (बीटीएस) की कुछ दिलचस्प झलकियां साझा की हैं। अपारशक्ति की ओर से जबरदस्त एक्शन सीन की कई तस्वीरें और क्लिप शेयर की गई। साथ ही उन्होंने एक रफ विलेन के लुक में अपनी तस्वीरें और सेट की एक झलक भी दिखाई। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'विलेन की तरह चिल कर रहा हूं!' 'आशिक बनाया आपने' के डायरेक्टर आदित्य दत्त ही इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। 'आशिक बनाया' फिल्म से ही हिमेश रेशमिया को पहचान मिली थी। आदित्य दत्त 'क्रैक', 'टेबल नंबर 21', और 'कमांडो' फ़्रैंचाइजी के लिए जाने जाते हैं। इस फ़िल्म को दीपक मुकुट और हुनर झमुकुट ने सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है, और इसमें जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह भी हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक ऐसे एक्शन अवतार में नजर आएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया; इसमें शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी होगी जो दर्शकों को पसंद आएगी। अपारशक्ति को आखिरी बार सौरभ शुक्ला की ओर से निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'जब खुली किताब' में देखा गया था। यह फिल्म शुक्ला के ही इसी नाम के स्टेज प्ले पर आधारित है। फिल्म में पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया एक बुजुर्ग जोड़े के रोल में हैं, जो शादी के 50 साल बाद तलाक लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद वह नवजोत गुलाटी की डायरेक्ट की गई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'बदतमीज गिल' में नजर आएंगे। इसमें वाणी कपूर, अपारशक्ति खुराना, परेश रावल, शीबा चड्ढा, रिचर्ड भक्ति क्लेन और मोनिका चौधरी हैं। आमिर खान की 'दंगल' से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद, अपारशक्ति (जो एक्टर आयुष्मान खुराना के छोटे भाई हैं) ने 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'स्त्री', 'लुका छुपी' और 'पति पत्नी और वो' जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स में काम किया।

सनकी लड़की का रोल करना चाहती हूं

कृति सेनन का कहना है कि अब वे लीक से हटकर किरदारों के जरिए खुद को चुनौती देने के लिए उत्साहित हैं। अभिनेत्री ने माना कि वे जाने-पहचाने किरदारों से आगे बढ़ना चाहती हैं और उन्हें खास तौर पर साइकोलॉजिकली इंटेंस किरदार पसंद हैं। उन्होंने कहा कि वे पर्दे पर 'साइको चिक' का रोल निभाना पसंद करेंगी।

'ऑब्सेशन' ने सोचने पर मजबूर किया कृति सेनन ने हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' के साथ बातचीत में उस तरह के किरदारों के बारे में बात की, जिन्हें वे भविष्य में आजमाना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल ड्रामा 'ऑब्सेशन' देखने के बाद उन्हें स्क्रिप्ट चुनने के अपने तरीके पर फिर से सोचने की प्रेरणा मिली। फिल्म के असर के बारे में बात करते हुए कृति ने कहा, 'जब मैंने 'ऑब्सेशन' देखी, तो मुझे लगा, 'अरे बाप रे, हमें सेफ खेलने की आदत छोड़नी होगी। हमें कुछ हटकर करना होगा'। इसने मुझे सच में बहुत उत्साहित किया। सनकी लड़की का किरदार निभाना चाहती हूं कृति सेनन एक 'साइको' लड़की का किरदार निभाना चाहती हैं। एक्ट्रेस ने जेंडाया जैसे स्टार्स को भी इसका क्रेडिट दिया, जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस मुश्किल किरदारों को निभा पाने की हिम्मत से प्रेरित किया है। कृति ने रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल हटकर किरदार निभाने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने कहा, 'मैं एक सनकी किरदार निभाना चाहती हूं'।

सेफ नहीं चलना

कृति सेनन ने कहा, 'मैं किरदारों को लेकर सेफ साइड में नहीं चलना चाहती। एक अभिनेत्री के रूप में, ऐसा जीवन जीना बहुत रोमांचक है, जो आपके जीवन से बिल्कुल अलग है और उस व्यक्ति का पता लगाना जो आप नहीं हैं। मैं पूरी तरह से किसी मानसिक रोगी का किरदार निभाना पसंद करूंगी'। कृति के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्हें 'कॉकटेल 2' में देखा गया।

'रामायण' का हिस्सा बनने का अहसास शब्दों से परे है

रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत फिल्म 'रामायण' का हिस्सा बनकर रकुल प्रीत सिंह बेहद खुश हैं। बीते दिन शनिवार को इस फिल्म का भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर रकुल प्रीत सिंह भी शामिल हुईं। फिल्म में काम करने को लेकर अभिनेत्री बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई है। रकुल प्रीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट को सिनेमा से भी आगे की एक यात्रा बताया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने 'रामायण' के भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट की झलकियां शेयर कीं। साथ ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बारे में बात की। इवेंट में रकुल प्रीत येलो कलर की ड्रेस में नजर आईं। उन्होंने लिखा है, 'एक ऐसी चीज का हिस्सा बनना सम्मान की बात है, जो जिंदगी और सिनेमा से भी कहीं बड़ी है। हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी रामायण। हम दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एहसास सचमुच शब्दों से परे है। आप सभी के हमारे साथ इस दुनिया में कदम रखने का बेसब्री से इंतजार है'। बता दें कि रकुल प्रीत सिंह को नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा की भूमिका में देखा जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में होंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता का रोल कर रही हैं। एक्टर यश रावण की अहम भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी।

टिया बाजपेयी की सिंगर-गीतकार के रूप में नई शुरुआत

हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री टिया बाजपेयी इन दिनों अपने नए म्यूजिक सिंगल 'नंबर 1' को लेकर चर्चा में हैं। इस गाने में उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि इसके बोल भी खुद लिखे हैं। टिया का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसके जरिए वह एक साथ अभिनेत्री, गायिका और गीतकार के रूप में दर्शकों के सामने आई हैं। टिया बाजपेयी ने अनुभव साझा करते हुए कहा, ''मेरे लिए कलाकार होने का मतलब कभी सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित रहना नहीं रहा। अभिनय और संगीत, दोनों ही मेरे दिल के बेहद करीब हैं। 'नंबर 1' के जरिए मुझे पहली बार इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने का मौका मिला। इस गाने के बोल लिखना और फिर उसी पर लीड एक्ट्रेस के तौर पर परफॉर्म करना बेहद संतोष देने वाला अनुभव रहा।''

उन्होंने कहा, ''किसी भी कलाकार के लिए खुद को नए रूप में पेश करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मैं खुश हूं कि अब दर्शक मुझे एक साथ अभिनेत्री, गायिका और गीतकार के रूप में देख रहे हैं। उम्मीद है कि वे मेरे नए रूप को भी उतना ही पसंद करेंगे, जितना अब तक मेरे काम को करते आए हैं।''

टिया ने गाने की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया, ''रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान मेरी फरारी रेत में फंस गई थी। प्रोडक्शन टीम मेरी ही फरारी का इस्तेमाल शूटिंग के लिए कर रही थी, इसलिए उसे बाहर निकालना जरूरी था। करीब नौ लोगों ने मिलकर कार को धक्का लगाया, तब जाकर वह रेत से बाहर निकली। शायद पहली बार किसी फरारी का इस्तेमाल प्रोडक्शन कार और मेरी निजी वॉर्डरोब कार के रूप में किया

आपत्तिजनक कंटेंट के सवाल पर निरहुआ बोले

भोजपुरी अभिनेता और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर लंबे समय से हो रही आलोचनाओं पर अपनी बात रखी है। आलोचकों ने भोजपुरी सिनेमा में महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने और अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए हैं। इस पर निरहुआ ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट के आधार पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आंकना गलत है। निरहुआ ने कहा कि हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री अलग-अलग तरह का कंटेंट बनाती है और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को ही अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में और हर तरह का कंटेंट बनता है जैसे बॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा और मराठी सिनेमा हैं, वैसे ही हर इंडस्ट्री दर्शकों के हर वर्ग की पसंद का ध्यान रखती है।'

भोजपुरी फिल्मों में ज्यादातर आपत्तिजनक कंटेंट होने के सवाल पर निरहुआ ने कहा, 'जब हम सिर्फ एक खास तरह के काम को ही दिखाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वहां बस वैसा ही काम हो रहा है। यह सच नहीं है। अच्छा और बुरा काम हर जगह होता है।' एक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कमियां हर इंडस्ट्री में होती हैं और उन्हें पूरी इंडस्ट्री की पहचान नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, 'लाख बुराइयां सबमें होती हैं। कोई भी इंसान कमियों से परे नहीं होता। ऐसा कोई बाग दिखा दीजिए जहां गुलाब में कांटे न हों। यह हर जगह होता है। बस कुछ चीजें अधिक दिखाई जाती हैं, इसलिए लोगों को लगने लगता है कि वहां बस वही सब है।'

भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक निरहुआ ने कई सफल फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, जिनमें 'निरहुआ रिक्शावाला', 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'पटना से पाकिस्तान', 'बॉर्डर', 'सिपाही', 'जिगरवाला' और 'निरहुआ चलल लंदन' शामिल हैं। खासकर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है। भोजपुरी फिल्मों के अलावा इस एक्टर ने हिंदी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में उन्हें ओटीटी सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 में देखा गया, जिसमें दर्शकों ने उनके काम को काफी पसंद किया। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने ही इस शो की खूब तारीफ की। इस शो में अमोल पाराशर, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन भी अहम भूमिकाओं में थे।

12-14 घंटे तक नकारात्मक किरदार में रहना आसान नहीं

टीवी अभिनेत्री जयति भाटिया लंबे समय से छोटे पर्दे पर दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहचान सबसे ज्यादा मजबूत रही है। इन दिनों वह टीवी शो 'जाने अनजाने हम मिले' में शारदा उर्फ शालिनी बत्रा का किरदार निभा रही हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।

पर्दे पर खलनायिका का किरदार निभाना जितना आसान दिखाई देता है, असल में उसे घंटों तक जीना किसी कलाकार के लिए बड़ी चुनौती है। जयति भाटिया ने इसी अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि डेढ़ साल से ज्यादा समय तक एक नकारात्मक किरदार निभाना उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक रहा है। टीवी शो 'जाने अनजाने हम मिले' में शारदा उर्फ शालिनी बत्रा का किरदार निगेटिव है। अभिनेत्री ने बताया कि कहानी में जैसे-जैसे नए मोड़ आते गए, वैसे-वैसे शारदा का नकारात्मक पक्ष भी मजबूत होता गया। ऐसे में रोजाना 12 से 14 घंटे तक उसी सोच और भावनाओं के साथ काम करना एक बड़ी चुनौती बन गया।

उन्होंने कहा, ''पिछले डेढ़ साल से ज्यादा समय से इस किरदार को निभाना मेरे अभिनय सफर का बेहद खास हिस्सा रहा है। हर नए एपिसोड और हर नए ट्रैक के साथ शारदा का स्वभाव और ज्यादा चालाक, साजिश करने वाला और नकारात्मक होता गया। ऐसे में हर दिन 12 से 14 घंटे तक उसी मानसिक स्थिति में बने रहना आसान नहीं होता। इस किरदार ने मेरे अभिनय के स्तर को काफी मजबूत बनाया है और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका दिया है।'' अभिनेत्री ने साफ किया कि वह शूटिंग खत्म होने के बाद खुद को किरदार से पूरी तरह अलग कर लेती हैं। उन्होंने कहा, ''जैसे ही पैकअप होता है, मैं शारदा को सेट पर ही छोड़ देती हूं और फिर दोबारा जयति बन जाती हूं। मेरे लिए यह जरूरी है, ताकि मैं अपनी निजी जिंदगी को इस किरदार से प्रभावित न होने दूं। अगर कलाकार ऐसा न करे तो लगातार नकारात्मक किरदार निभाना मानसिक रूप से काफी थका देने वाला हो सकता है।''

असली जिंदगी में मैं ऐसी नहीं हूं

सेट पर सभी कलाकार अच्छी तरह जानते हैं कि शारदा सिर्फ किरदार है, असली जिंदगी में मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं। कैमरे के पीछे हम सभी साथ बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। इस माहौल की वजह से मुझे अपने किरदार के तनाव से बाहर आने में भी काफी मदद मिलती है।''

अभिनेत्री ने दर्शकों की प्रतिक्रिया पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ''जब दर्शक शारदा पर गुस्सा होते हैं या उसके कामों की आलोचना करते हैं, तो मैं इसे अपनी तारीफ मानती हूं। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे इस किरदार में पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। मैं ऐसी प्रतिक्रियाओं को कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेती। बल्कि यही बातें मुझे शारदा के किरदार को और ज्यादा सच्चाई और मजबूती के साथ निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। मेरे लिए एक मजबूत नकारात्मक किरदार निभाने का यही सबसे बड़ा इनाम है।''

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से कबीरधाम के बच्चों को मिली नई जिंदगी की उम्मीद

नि :शुल्क ईको कार्डियोग्राफी शिविर में 53 बच्चों की जांच, 18 बच्चों का होगा नि :शुल्क ऑपरेशन, उप मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर लगा विशेष हृदय जांच शिविर

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय संबद्ध शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में रायपुर के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत निःशुल्क ईको कार्डियोग्राफी जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 53 बच्चों की विशेषज्ञ जांच की गई, जिनमें 18 बच्चों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इन सभी बच्चों का उपचार शासन की व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा।

समय पर पहचान से मिलेगा बेहतर इलाज : इस पहल का उद्देश्य जन्मजात एवं अन्य हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के माध्यम से चिन्हित बच्चों का ऑपरेशन और उपचार निःशुल्क कराया जाएगा, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे के इलाज में बाधा न बने।

कलेक्टर ने किया निरीक्षण, नियमित शिविरों के दिए निर्देश : कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग को ऐसे विशेष जांच शिविर नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हृदय रोग से पीड़ित प्रत्येक बच्चे का उपचार बिना किसी विलंब के सुनिश्चित किया जाए।

विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी सेवाएं : शिविर में रायपुर से आए पीडियाट्रिक काडियोलॉजिस्ट डॉ. चन्द्रकांत उसेंडी ने बच्चों की ईको काडियोग्राफी जांच की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी शिविर में उपस्थित रहकर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया का अवलोकन किया।

चिरायु योजना से मिल रहा निःशुल्क उपचार : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। गंभीर बीमारी पाए जाने पर बच्चों को शासन द्वारा अनुबंधित शासकीय एवं निजी अस्पतालों में, आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर भी निःशुल्क उपचार एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

हृदय रोग के संकेतों को न करें नजरअंदाज : शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सलिल मिश्रा ने बताया कि दूध पीते समय जल्दी थक जाना, अत्यधिक पसीना आना, होंठ या नाखून नीले पड़ना, वजन नहीं बढ़ना, तेज सांस चलना, थोड़े परिश्रम में सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर आना या बेहोश होना हृदय रोग के प्रमुख संकेत हो सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें और समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं।

खास खबर

नव दंपत्तियों को विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से बचा समय, श्रम और पैसा

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

विवाह के बाद आवश्यक शासकीय दस्तावेजों में विवाह प्रमाण पत्र का विशेष महत्व होता है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नव दंपत्तियों के लिए विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम हो गई है। सेवा सेतु केंद्र में आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित समय में विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

कबीरधाम जिले के ग्राम राम्हेपुर निवासी फलित पुरेना और उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका पुरेना ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया। लगभग दो माह पूर्व विवाह के बंधन में बंधे इस नव दंपत्ति को विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र में आधार कार्ड, विवाह के फोटो, शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। सेवा सेतु केंद्र के कमर्चारियों ने सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन कर आवेदन संबंधित विभाग को भेज दिया। विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसे नव दंपत्ति ने सेवा सेतु केंद्र से प्राप्त किया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध रही।

फलित पुरेना ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। न कहीं भटकना पड़ा और न ही किसी प्रकार की परेशानी हुई। इससे समय, श्रम और पैसे तीनों की बचत हुई। एक ही स्थान पर आवेदन जमा हुआ, दस्तावेजों का पंजीयन हुआ और निर्धारित समय में प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु केंद्र जैसी व्यवस्था से आम नागरिकों को समय पर और सहज तरीके से शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

सेवा सेतु में 86 से बढ़कर 441 सेवाएं : पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं। इनमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का एकीकरण किया गया है। तीस से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोटर्लों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

जिले में सेवा सेतु केन्द्रों का विस्तार : वर्तमान में जिले के सभी 08 तहसील कार्यालयों में सेवा सेतु केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले के 332 सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा हैं। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना : प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 5 अगस्त तक

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत सत्र 2026-27 में प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों की सूची एवं तिथि जारी की गई है। जिसके अनुसार 5 अगस्त 2026 तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक काउसलिंग सूची में दर्शित आबंटित प्रयास आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। प्रकाशित सूची का अवलोकन वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in/ पर किया जा सकता है। विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने कहा गया है। विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) उत्तीर्ण अंक सूची, प्रधानपाठक या प्राचार्य द्वारा जारी (कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत होने का) सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, 10 रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक वर्ग अन्तर्गत होने संबंधी नोटरी का सत्यापन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमाण पत्र एवं विशेष श्रेणी से चयनित विद्यार्थियों को कांउसलिंग की तिथि को दिव्यांगता, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे होने, अनाथ बच्चे होने, विधवा माता के बच्चे होने, परित्यक्ता महिला के बच्चे होने, देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस, अर्द्धसैनिक, सशस्त्र बल, शहीद सैनिक के बच्चे होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।

नगर पालिका के नवनियुक्त एल्डरमैनों ने ली शपथ विकास कार्यो का किया भूमिपूजन और लोकार्पण

विधायक दीपेश साहू ने ई-रिक्शा कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा बुधवार को गांधी भवन स्थित बेसिक स्कूल मैदान में नवनियुक्त एल्डरमैनों के शपथ ग्रहण समारोह, विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण तथा स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ई-रिक्शा आधारित कचरा संग्रहण वाहनों के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की, जबकि रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्षदों, नगर पालिका के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की।

समारोह में राकेश मोहन शर्मा, सावित्री रजक, तारण सिंह राजपूत एवं कमलेश वर्मा ने एल्डरमैन के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने सभी नवनियुक्त एल्डरमैनों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद विधायक दीपेश साहू एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

जनता की सेवा और वार्डो के विकास को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : दीपेश साहू

विधायक दीपेश साहू ने कहा कि एल्डरमैन का दायित्व केवल एक पद नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सेवा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी एल्डरमैन अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके निराकरण के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नगर का समग्र विकास जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ई-रिक्शा आधारित कचरा संग्रहण से मजबूत होगी स्वच्छता व्यवस्था

कार्यक्रम के दौरान नगर की स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 8 ई-रिक्शा आधारित कचरा संग्रहण वाहनों को विधायक दीपेश साहू एवं जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में नागरिकों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ई-रिक्शा के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण किया जाएगा, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने नागरिकों से गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा निर्धारित वाहनों में ही कचरा देने की अपील की।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अंतर्गत विभिन्न वार्डों एवं प्रमुख चौक-चौराहों में लगभग ?3 करोड़ 23 लाख 57 हजार की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया। इनमें चबूतरा निर्माण, वाचनालय का जीणीद्धार, प्रकाश व्यवस्था, विभिन्न चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड के पीछे गार्डन का विकास, एसएलआरएम/एमआरएफ प्लांट निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हाईमास्ट लाइट स्थापना तथा ई-रिक्शा क्रय जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

नगर के विकास के लिए सभी मिलकर करेंगे कार्य : विजय सिन्हा

नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नगर पालिका परिषद शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नवनियुक्त एल्डरमैनों के जुड़ने से परिषद और अधिक मजबूत होगी तथा सभी जनप्रतिनिधि मिलकर वार्डो की समस्याओं के समाधान एवं शहर के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा आधारित कचरा संग्रहण व्यवस्था से सफाई व्यवस्था में सकारात्मक सुधार आएगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, होरिलाल सिन्हा, शहर मंडल अध्यक्ष युगल देवांगन, पार्षद पंचू साहू, नीतू कोठारी, गौरव साहू, आकिब मलकानी, राजकुमार खांडे, रवि मुलवानी, पार्षद प्रतिनिधि रोशन दत्ता, प्रज्ञा निर्वाणी, मीनू पटेल, पिंकी नेमा गुप्ता, संदीप यादव, दोहाई लाल वर्मा, राजेश शर्मा, लच्छन वर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

बेमेतरा जिले का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त होने पर सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंत्री बघेल का जताया आभार

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं नवागढ़ विधायक दयालदास बघेल द्वारा जिला पंचायत, बेमेतरा के लिए सुरेन्द्र सिंह ठाकुर को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों में हर्ष का वातावरण है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए श्री ठाकुर ने मंत्री दयालदास बघेल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए सम्मान के साथ-साथ जनसेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्री दयालदास बघेल ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त कर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। यह केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि उन सभी समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो वर्षो से संगठन और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वे मंत्री दयालदास बघेल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा जिला पंचायत के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

श्री ठाकुर ने आगे कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, विकास कार्यों में गति आए तथा जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा नेतृत्व एवं विशेष रूप से मंत्री दयालदास बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर सम्मानित करने की परंपरा संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है।

शुभकामनाएँ देने वालो में जिला अध्यक्ष अजय साहू , खंडसरा मंडल अध्यक्ष गयाराम चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष राजेश जैन,राजाराम ठाकुर, सरपंच छिरहा मृत्युंजय सिंह, कठौतिया सरपंच राजाराम चंद्राकर , सोन सिंह शामिल रहे। अंत में सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने सभी वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

लखपति दीदी अभियान में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रदेश में बना मिसाल

लक्ष्य से 70 .5 प्रतिशत अधिक महिलाओं को मिली आर्थिक सशक्तता

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में लखपति दीदी जिला स्तरीय विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल सहित कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारंभ में जिला परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) उमेश कुमार तिवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लखपति दीदी अभियान के लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के तीन वर्षीय संयुक्त लक्ष्य 12,111 के विरुद्ध जिले में 20,650 लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से 8,539 अधिक है, जो लक्ष्य की तुलना में लगभग 70.5 प्रतिशत अधिक उपलब्धि को दर्शाती है। साथ ही वर्ष 2026-29 तक आगामी तीन वर्षों में बिहान से जुड़े सभी स्व-सहायता समूह सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 9,000 नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

बैठक में बताया गया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले में समूह सदस्यों द्वारा नवाचार के रूप में 16 सब्जी नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इन नर्सरियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सब्जी पौधे तैयार कर महिला किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक इन नर्सरियों से लगभग 14 लाख सब्जी पौधे तैयार किए जा चुके हैं, जिससे महिला समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार स्वर्ण उपज एफपीओ में जिले के लगभग 12 हजार स्व-सहायता समूह सदस्य शेयरधारक के रूप में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में नाफेड के माध्यम से कृषि उपज जैसे चना एवं अरहर का समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार मूल्य की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं बैंक लिंकेज एवं सस्ते ऋण की सुविधाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार भी कर रही हैं।

बैठक में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने निर्देश दिए कि समूह सदस्यों को उपलब्ध बैंक लिंकेज राशि का अधिकतम उपयोग आजीविका गतिविधियों में किया जाए। उन्होंने वनांचल क्षेत्रों में भी सब्जी नसर्री की स्थापना कर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने तथा विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और जिले में लखपति दीदी अभियान को नई गति मिलेगी।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों की योजनाओं के माध्यम से स्व-सहायता समूह की महिलाओं को लाभान्वित करने एवं उन्हें आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत करना रहा।

समीक्षा बैठक | कलेक्टर ने आईसीडीएस, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

स्वस्थ और कुपोषण मुक्त बेमेतरा की दिशा में और तेज हों प्रयास-कलेक्टर प्रतिष्ठा

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, कुपोषण एवं एनीमिया नियंत्रण अभियान में गति लाने तथा आमजन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास , स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों एवं लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध एवं परिणाममूलक कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब प्रत्येक पात्र हितग्राही तक उनका लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में गंभीर कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की पहचान, उनके उपचार एवं सतत निगरानी, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य परीक्षण, एनीमिया नियंत्रण, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु देखभाल तथा पोषण पुनर्वास केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से नियमित फॉलोअप करें तथा प्रत्येक प्रकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, पूरक पोषण आहार वितरण, बच्चों के नियमित वजन एवं ऊंचाई मापन, पोषण ट्रैकर एप में समय पर जानकारी दर्ज करने तथा हितग्राहियों के गृह भ्रमण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी सेवाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी पात्र हितग्राही को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों एवं दवाइयों की उपलब्धता तथा विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। आयुष विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने आयुष चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली, औषधियों की उपलब्धता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा गतिविधियों तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए इसकी सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए।

बैठक के दौरान विभागवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, नियमित फील्ड मॉनिटरिंग करने तथा सभी योजनाओं की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सभी योजनाओं का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और इसके लिए सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।बैठक में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर यादव के निर्देश पर शासकीय भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में घुमका तहसील अंतर्गत ग्राम पटेवा में राजस्व विभाग की टीम ने शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्राम पटेवा निवासी ऐमन कुमार ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण अपने खेत तक आवागमन एवं कृषि कार्य में हो रही परेशानी से अवगत कराया था। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने तथा आवेदक की समस्या का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौतम कुमार पाटिल के नेतृत्व में तहसीलदार मुकेश ठाकुर, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकर्ता जगदीश साहू द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने कहा कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्कूल-कॉलेज के पास हेरोइन बेचते आरोपी गिरफ्तार 8.49 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल और बाइक किया जप्त

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना खुर्सीपार पुलिस ने आईटीआई मैदान के पास अवैध रूप से हेरोइन बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को नशीला पदार्थ बेच रहा था।

पुलिस को 23 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आई.टी.आई. मैदान, खुर्सीपार के पास एक युवक हेरोइन की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया।

जप्त हुआ सामान : पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जसराज सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, छावनी, भिलाई बताया। तलाशी में उसके पास से 8.49 ग्राम हेरोइन, बिक्री रकम 1,050 रुपये, 2 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद कर जप्त की गई।

NDPS एक्ट में मामला दर्ज : आरोपी के खिलाफ थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 295/2026 धारा 8, 21(), 27अ टउ्रूद्धर अू३ के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी आईटीआई मैदान और आसपास के स्कूल-कॉलेजों के पास युवाओं को छोटी-छोटी मात्रा में हेरोइन बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गंजपारा में 300 नशीली टेबलेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने गंजपारा क्षेत्र में घेराबंदी कर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 300 नग नशीली टेबलेट के साथ 2 धारदार हथियार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 1 लाख 36 हजार रुपये है। पुलिस को 23 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंजपारा स्थित प्रियंका बोरवेल्स के पीछे मैदान में 2 व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। वहां से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम दिपेश उर्फ आयुषदीप, उम्र 21 वर्ष, निवासी उत्कल कॉलोनी, गंजपारा और कृष्णा कुमार सेन, उम्र 19 वर्ष, निवासी डिपरापारा, दुर्ग बताया। तलाशी में दिपेश के पास से 150 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, 1 धारदार हथियार और 1 ओप्पो मोबाइल मिला। वहीं कृष्णा के कब्जे से 150 नग नशीली टेबलेट, 1 धारदार हथियार और 1 आईफोन रए 2020 मिला। कुल 300 नग टेबलेट की कीमत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 411/2026 धारा 21(ख) एनडीपीएस अधिनियम और धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण अजमानतीय होने के कारण दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सार्वजनिक स्थान पर नशीली टेबलेट लेकर ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और अपने बचाव के लिए हथियार भी साथ रखे हुए थे। दुर्ग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों से मारपीट, प्रधान पाठिका सस्पेंड : ग्रामीणों और अभिभावकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-पाटन

जिले के पाटन विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतोरा की प्रधान पाठिका ममता शांडिल्य को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधान पाठिका पर छात्रों से मारपीट व अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। इस मामले में ग्रामीणों व अभिभावकों कलेक्टर और शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) दुर्ग ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। विभागीय जांच में पुष्टि होने के बाद शिक्षा संभाग दुर्ग के संयुक्त संचालक ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी किया।

ग्रामीणों के अनुसार 18 जुलाई को एक छात्र को कथित रूप से कांटेदार डंडे से पीटा गया, जिससे उसके हाथ में चोट आई। आरोप है कि स्कूल के पीछे जाने का कारण पूछने पर उसके साथ मारपीट की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा चुका था। स्कूल के एक छात्र ने आरोप लगाया कि प्रधान पाठिका अक्सर कहती थीं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो टीसी लेकर चले जाओ। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे चाय बनवाई जाती थी और निजी काम भी कराए जाते थे। इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठिका ममता शांडिल्य को सस्पेंड कर दिया गया।

आदेश में कहा गया है कि प्रधान पाठिका के व्यवहार से विद्यालय की छात्राओं में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था। पालकों और जनप्रतिनिधियों में भी उनके प्रति नाराजगी थी। विभाग के अनुसार इससे स्कूल का शैक्षणिक और अनुशासनात्मक वातावरण प्रभावित हुआ। प्रधान पाठिका का आचरण शासकीय दायित्वों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाहीपूर्ण और स्वैच्छाचारी था। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग रहेगा।

ट्रेन शुरू होने के बाद चढ़ने के प्रयास में फिसला यात्री, चपेट में आने से मौत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन चढ़ने के प्रयास में फिसल कर उसी ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की मौत हो गई। गुरूवार सुबह प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के बीच जैसे यात्री फिसलकर गिरा तो अफरार तफरी मच गया। ट्रेन निकलने के बाद एंबुलेंस की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 6:15 बजे ट्रेन संख्या 22845 पुणे- हटिया एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर तीन पर खड़ी हुई थी। जब ट्रेन चलने लगी तब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक वार्ड नंबर 58 साईं मंदिर के पास कमर्चारी नगर दुर्ग निवासी संदीप कुमार सिन्हा (58) ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिरकर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में फंस गये।

ट्रेन उनके एक पैर के ऊपर से गुजर गई जिससे पैर कट गया। गंभीर रूप से घायल संदीप कुमार सिन्हा को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बताया गया कि संदीप कुमार सिन्हा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की रायपुर शाखा में एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थ थे और कार्यालयीन कार्य से ट्रेन के माध्यम से रायपुर जा रहे थे। जीआरपी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100